



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]  
No. 26]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 1, 1978/आषाढ़ 10, 1900  
NEW DELHI, SATURDAY, JULY 1, 1978/ASADHA 10, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)  
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India  
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities  
(other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 30 मई, 1978

जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि  
के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं. 76/उड़ीसा-वि.सं./142/77]

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 30th May, 1978

कां.भा. 1860.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उड़ीसा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 142 चम्पुआ (अ.ज. जा.) निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महेन्द्र नाग ..... लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तर्धान बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रयत्न स्पष्टीकरण नहीं दिया है, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यावहारिक नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एन.डी.आर. उक्त श्री महेन्द्र नाग को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा प्रथम विधान परिषद् के सदस्य चुने

293 GI/78—1

S.O. 1860.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mahendra Nag a contesting candidate for general election to the Orissa Legislative Assembly held in June, 1977 from 142-Champua (ST) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mahendra Nag to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/OR-LA, 142/77]

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 1978

क्रा० जा० 1861.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1978 में हुए केरल राज्य के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 78-कुन्नाथुनाद सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पी० के० कुमारन, पडिकापरम्बील, करीमुकल काकोनी शाकघर पुथनकुज, जिला एरनाकुलम, केरल राज्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री पी० के० कुमारन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० केरल-बी० सं०/78/77]

ORDER

New Delhi, the 5th June, 1978

S.O. 1861.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri P. K. Kumaran, Padikkaparambil, Karimukul Colony, P.O. Puthencruz, District Ernakulam, Kerala State, a contesting candidate for general election to the Kerala Legislative Assembly from 78-Kunnathunad assembly constituency, held in March, 1977 has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri P. K. Kumaran to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/78/77]

आदेश

क्रा० जा० 1862.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 9-सतारी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मुजावर शेक अली इब्राहिम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मुजावर शेक अली इब्राहिम को संसद के

किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० गोवा-बि० सं०/9/77]

ORDER

S.O. 1862.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mujawar Shaik Ali Ibrahim a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in June, 1977 from 9-Satari Assembly Constituency, has failed to lodge any account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mujawar Shaik Ali Ibrahim to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. Goa-LA/9/77]

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 1978

क्रा० जा० 1863.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 1-परनम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पदनेकार शान्ताराम पुरशोत्तम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री पदनेकार शान्ताराम पुरशोत्तम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० गोवा/बि० सं०/1/77]

ORDER

New Delhi, the 6th June, 1978

S.O. 1863.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Pednekar Shantaram Purshottam a contesting candidate for General Election to the Legislative Assembly held in June, 1977 from 1-Pernem (SC) Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Pednekar Shantaram Purshottam to be disqualified for being

chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. Joa-LA/1/77]

प्रादेश

नई दिल्ली, 8 जून 1978

क्रा० आ० 1864.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 50-चिट्ठर सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मेम्बुली राघवन, सम्पादक, एड्युल दैनिक समाचार पत्र, त्रिचुर-4 केरल राज्य, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा वाञ्छित करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण यान्त्रायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री मेम्बुली राघवन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की शारोख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं० केरल-वि० सं०/50/77]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 8th June, 1978

S.O. 1864.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mambully Raghavan, Editor, Edyval Daily, Trichur-4 (Kerala), a contesting candidate for general election to the Kerala Legislative Assembly held in March, 1977 from 50-Chittur assembly constituency, has failed to lodge the account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mambully Raghavan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/50/77]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

## गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सहाय विभाग

नई दिल्ली, 16 जून, 1978

क्रा० आ० 1865.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (6) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री एन० चन्द्रशेखरन, अधिवक्ता, मद्रास को, श्री के० वीरास्वामी, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय के बिहड़ प्राबन्धक पुनरीक्षण वाचिका संख्या 265/78 तथा/अथवा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना नियमित मामला संख्या 1/76-सी०आई०यू०-दिल्ली

से उत्पन्न अन्य सभी मामलों में राज्य की ओर से मद्रास उच्च न्यायालय में उपस्थित होने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है ।

[संख्या 225/25/78-ए०वी०डी०-II]

टी०के० सुब्रमणियन, अवर सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel &amp; Administrative Reforms)

New Delhi, the 16th June, 1978

S.O. 1865.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri N. Chandrasekharan, advocate, Madras, as a Special Public Prosecutor to appear on behalf of the State in the Madras High Court in Criminal Revision petition No. 265/78 and/or all other matters arising out of Delhi Special Police Establishment Regular Case No. 1/76-CIU-Delhi against Shri K. Veeraswamy, former Chief Justice of Madras High Court.

[No. 225/25/78-AVD-II]

T. K. SUBRAMANIAN, Under Secy.

(राज्यभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 17 जून, 1978

क्रा० आ० 1866.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों को जिनके कर्मचारी व्यू ने हिन्दी का कारिभाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. श्रम मंत्रालय ।
2. भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय ।

[संख्या 12022/1/78-रा०भा० (ख-2)]

हरिबाबू कंसल, उप सचिव

(Department of Official Language)

New Delhi, the 17th June, 1978

S.O. 1866.—In pursuance of sub-rule (4) or rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following Ministries/Departments, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Ministry of Labour.
2. Secretariat of Election Commission of India.

[No. 12022/1/78-O.L. (B-2)]

H. B. KANSAL, Dy. Secy.

## विस्त मंत्रालय

(राज्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1978

प्राय-कर

क्रा०आ० 1867.—केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री बाबु राजा मठ, सोन्डा" को निर्धारण वर्ष 1978-83 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनाय अधिसूचित करती है ।

[सं० 211/फा०सं० 6 197/73/77 आ०क० ( -1)]

**MINISTRY OF FINANCE**  
(Department of Revenue)

New Delhi, the 6th February, 1978  
(INCOME-TAX)

**S.O. 1867.**—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 'Sri Vadiraja Mutt, Sonda' for the purpose of the said section for and from the assessment year 1962-63.

[No. 2161/F. No. 197/73/77-IT(AI)]

**कांआ० 1868.**—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री काशी मठ संस्थान, मुम्बई" को निर्धारण वर्ष 1971-72 से 1976-77 तक के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 2163 (फा० सं० 197/100/77-आ०क(ए1))]

**S.O. 1868.**—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 'Shri Kashi Mutt Sansthan, Bombay' for the purpose of the said section for the assessment years 1971-72 to 1976-77.

[No. 2163/F. No. 197/100/77-IT(AI)]

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1978

आय कर

**कांआ० 1869.**—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री गजानन महाराज संस्थान, शेगांव" को निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 2204/फा० सं० 197/35/77-आ०क(ए1)]

New Delhi, the 28th February, 1978

Income-Tax

**S.O. 1869.**—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 'Shri Gajanan Maharaj Sansthan Shegaon' for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1974-75.

[No. 2204 (F. No. 197/35/77-IT(AI))]

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1978

आय कर

**कांआ० 1870.**—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री वनमामलाई मठ, नमगुनेरी" को निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 2247/फा० सं० 197/158/77-आ०क(ए1)]

एम शास्त्री, अवसर सचिव

New Delhi, the 31st March, 1978

INCOME-TAX

**S.O. 1870.**—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 'Sri Vanamamalai Mutt, Nanguneri' for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1973-74.

[No. 2247/F. No. 197/158/77-IT(AI)]

M. SHASTRI, Under Secy.

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 26 मई, 1978

आयकर

**कांआ० 1871.**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) से श्रद्धांजलि केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री के० नरसिम्ह को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना उस तारीख से लागू होगी जिस तारीख से श्री के० नरसिम्ह कर वसूली अधिकारी का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

[सं० 2317 (फा० सं० 404/25/78-आ०क(म०क०))]

एच० वेंकटरामन्, उप सचिव

(Department of Revenue)

New Delhi, the 26th May, 1978

INCOME TAX

**SO. 1871.**—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri K. Narasimhan being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri K. Narasimhan takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 2317 (F. No. 404/25/78-ITCC)]

H. VENKATARAMAN, Dy. Secy.

(आयिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 15 जून, 1978

**कांआ० 1872.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पुनिया के अध्यक्ष के रूप में श्री डी०सी० वर्मा को नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के "30 जून, 1978" प्रकों, प्रकरणों और शब्द के स्थान पर "31 दिसम्बर 1978" शब्द, प्रकरण और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एक० 3-38/77 आ०आ० बी०]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 15th June, 1978

**S.O. 1872.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 21st February, 1978 relating to the appointment of Shri D. C. Verma, as the Chairman of the Kosi Kshetriya Gramin Bank, Purnea, namely:—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 3-38/77 RRB]

**कांआ० 1873.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर (उ०प्र०) के

अध्यक्ष के रूप में श्री बी०एन० राय की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1971 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-58/76-ए०सी०]

**S.O. 1873.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri B. N. Rai, as the Chairman of the Bhagirath Gramin Bank, Sitapur (U.P.), namely:—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-58/76-AC]

**का०आ० 1874.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा शेखावटी ग्रामीण बैंक, सीकर के अध्यक्ष के रूप में श्री प्रार० जी० पुरी की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-81/76-ए०सी०]

**S.O. 1874.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri R. G. Puri, as the Chairman of the Shekhawati Gramin Bank, Sikar, namely:—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-81/76-AC]

**का०आ० 1875.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली के अध्यक्ष के रूप में श्री बलराम मिश्र की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-82/76-ए०सी०]

**S.O. 1875.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri Balram Mishra, as the Chairman of the Marwar Gramin Bank, Pali, namely:—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-82/76-AC]

**का०आ० 1876.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बोलंगीर प्रांचलिक ग्राम्य बैंक, बोलंगीर के अध्यक्ष के रूप में श्री गोलक बिहारी सारंगी, की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-86/75-ए०सी०]

**S.O. 1876.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri Golak Bihari Sarangi, as the Chairman of the Bolangir Aanchalik Gramya Bank, Bolangir, namely:—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-86/75-AC]

**का०आ० 1877.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पुरी ग्राम्य बैंक, पिपली के अध्यक्ष के रूप में श्री सुरेन्द्र महन्ती की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-87/75-ए०सी०]

**S.O. 1877.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri Surendra Mahant, as the Chairman of the Puri Gramya Bank, Pipli, namely:—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-87/75-AC]

**का० आ० 1878.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक, जैपोर के अध्यक्ष के रूप में श्री पी० नायक की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-88/76-ए० सी०]

**S.O. 1878.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment

of Shri P. Nayak, as the Chairman, of the Koraput-Panchabati Gramya Bank, Jaypore, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-88/76-AC]

का० आ० 1879.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मल्लभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा के अध्यक्ष के रूप में श्री प्रताप चक्रवर्ती की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-94/75-ए० सी०]

S.O. 1879.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri Pratap Chakraborty, Chairman, Mallabhum Gramin Bank, Bankura, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-94/75-AC]

का०आ० 1880.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर के अध्यक्ष के रूप में श्री के० पी० लाल की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-132/76-ए० सी०]

S.O. 1880.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri K. P. Lal as the Chairman of the Monghyr Kshetriya Gramin Bank, Monghyr, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-132/76-AC]

का०आ० 1881.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बुन्देलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़ के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० एम० बाधवाणी की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-138/76-ए० सी०]

S.O. 1881.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri S. M. Wadhvani, as the Chairman of the Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank, Tikamgarh, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. 4-138/76-AC]

का०आ० 1882.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा रीवा-सीधी ग्रामीण बैंक, रीवा के अध्यक्ष के रूप में श्री बी० डी० नारंग की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-139/76-ए० सी०]

S.O. 1882.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976, (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri B. D. Narang, as the Chairman of the Rewa-Sidhi Gramin Bank, Rewa, namely :—

In the said notification for the figures, letter and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 139/76-AC]

का०आ० 1883.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पण्ड्यान ग्राम्य बैंक, सतूर के अध्यक्ष के रूप में श्री टी० प्रार० कल्लापिरान की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-140/76-ए० सी०]

S.O. 1883.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976, (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977, relating to the appointment of Shri T. R. Kallapiran, as the Chairman of the Pandyan Gramya Bank, Sattur, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-140/76-AC]

का०आ० 1884.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कम्पानूर के अध्यक्ष के रूप में श्री सी० सी० प्रार० कामथ की नियुक्ति करती है और 1 जुलाई, 1978 से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसमें उक्त श्री सी० सी० प्रार० कामथ, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं० एफ० 3-35/77-प्रार० आर० बी०]

**S.O. 1884.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri C. C. R. Kamath, as the Chairman of the North Malabar Gramin Bank, Cannanore and specifies the period commencing on the 1st July, 1978 and ending with the 31st December, 1978 as the period for which the said C. C. R. Kamath shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-35/77-RRB]

का०भा० 1885.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा हरयाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० के० खन्ना की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० एक० 4-14/75-ए० सी०]

**S.O. 1885.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976, (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri S. K. Khanna, as the Chairman, of the Haryana Kshetriya Gramin Bank, Bhiwani namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-14/75-AC]

का०भा० 1886.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मगध ग्रामीण बैंक, गया के अध्यक्ष के रूप में श्री प्रसाद की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० एक० 4-80/76-ए० सी०]

**S.O. 1886.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976, (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri R. K. Prasad, as the Chairman of the Magadh Gramin Bank Gaya, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-80/76-AC]

का०भा० 1887.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा वैशाखी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष के रूप में श्री ए० के० सिन्हा की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० एक० 4-135/76-ए० सी०]

**S.O. 1887.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976, (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri N. K. Sinha, as the Chairman of the Vaishali Kshetriya Gramin Bank, Muzaffarpur, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-135/76-AC]

का०भा० 1888.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा राजलसीमा ग्रामीण बैंक कुरुपा के अध्यक्ष के रूप में श्री कुरुसागर कुंदे की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० एक० 4-83/76-ए० सी०]

**S.O. 1888.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976, (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri Kurupasagar Kunde, as the Chairman of the Rayalaseema Grammeena Bank, Cuddapah, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-83/76-AC]

का०भा० 1889.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक, फर्रुखाबाद के अध्यक्ष के रूप में श्री गोवर्धन दास गोयल को नियुक्त करती है और 1 जुलाई, 1978 से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि को, उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसमें श्री गोवर्धन दास गोयल अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[सं० एक० 3-16/77-प्रार० प्रार० बी०]

**S.O. 1889.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Govardhan Das Goyal as the Chairman of the Farrukhabad Gramin Bank, Farrukhabad and specifies the period commencing on the 1st July, 1978 and ending with 31st December, 1978 as the period for which the said Shri Govardhan Das Goyal shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-16/77-RRB]

का०भा० 1890.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होंगगाबाद के अध्यक्ष के रूप में श्री ए० एम० कोर्ले की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० एक० 3-8/77-प्रार० प्रार० बी०]

**S.O. 1890.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976, (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri A. M. Korde, as the Chairman of Kshetriya Gramin Bank, Hoshangabad, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 3-8/77-RRB]

**क्र० आ० 1891.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मोतीहारी के अध्यक्ष के रूप में श्री शिव शर्मा की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एक० 4-69/75 ए० सी०]

**S.O. 1891.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976, (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri Shiv Sharma, as the Chairman of the Champaran Kshetriya Gramin Bank, Motihari, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-69/75-AC]

**क्र० आ० 1892.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नागार्जुन ग्रामीण बैंक खम्माम के अध्यक्ष के रूप में श्री वाई० बी० सत्यनारायण की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एक० 3-19/77 आर० आर० बी०]

**S.O. 1892.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976, (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri Y. V. Satyanarayana Murthy as the Chairman of the Nagarjuna Gramina Bank, Khammam, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 3-19/77-RRB]

**क्र० आ० 1893.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा हिमाचल ग्रामीण बैंक, मण्डी के अध्यक्ष के रूप में श्री के० एस० राजपूत की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक

31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एक० 4-136/76 ए० सी०]

**S.O. 1893.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976, (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri K. S. Rajput, as the Chairman of the Himachal Gramin Bank, Mandi, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-136/76-AC]

**क्र० आ० 1894.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री विशाख ग्रामीण बैंक, श्री काकुलम के अध्यक्ष के रूप में श्री डी० आर० के० पटनायक की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एक० 4-84/76 ए० सी०]

**S.O. 1894.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976, (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri D. R. K. Patnaik, as the Chairman of the Sri Visukha Gramina Bank Srikakulam, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-84/76-AC]

**क्र० आ० 1895.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा संथाल परगना ग्रामीण बैंक दुमका के अध्यक्ष के रूप में श्री बी० के० घोष की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एक० 4-134/76 ए० सी०]

**S.O. 1895.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976, (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri B. K. Ghosh, as the Chairman of the Santhal Parganas Gramin Bank, Dumka, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-134/76-AC]



का० आ०.—1896 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मयूरक्षी ग्रामीण बैंक, सूरि के अध्यक्ष के रूप में श्री के० एस० बनर्जी की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एक० 4-75/76-ए० सी०]

**S.O. 1896.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976, (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri K. S. Banerjee, as the Chairman of the Mayurakshi Gramin Bank, Suri, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-75/76-AC]

का० आ० 1897.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी के अध्यक्ष के रूप में श्री कंवर वीरेन्द्र सिंह गुप्त की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एक० 4-93/75-ए० सी०]

**S.O. 1897.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri Kanwar Virendra Singh Gupta, as the Chairman of the Barabanki Gramin Bank, Barabanki, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-93/75-AC]

का० आ० 1898.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, बेलारी के अध्यक्ष के रूप में श्री एम० डी० प्रभु की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1978 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एक० 3-9/77-आर० आर० बी०]

**S.O. 1898.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976, (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 4th February, 1978 relating to the appointment of Shri M. D.

Prabhu, as the Chairman of the Tungabhadra Gramin Bank, Bellary, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 3-9/77-RRB]

का० आ० 1899.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० आर० शुकला की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एक० 3-40/77-आर० आर० बी०]

**S.O. 1899.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 18th February, 1978 relating to the appointment of Shri S. R. Shukla, as the Chairman of Ballia Kshetriya Gramin Bank, Ballia, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 3-40/77-RRB]

का० आ० 1900.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष के रूप में श्री एच० एम० शारदा की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एक० 4-79/76-ए० सी०]

**S.O. 1900.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri H. M. Sharda, as the Chairman of the Bilaspur-Raipur Kshetriya Gramin Bank, Bilaspur, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-79/76-AC]

का० आ० 1901.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कटक ग्राम्य बैंक, कटक के अध्यक्ष के रूप में श्री स्वरूप चन्द्र दास की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एक० 4-76/76-ए० सी०]

**S.O. 1901.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri Swarup Chandra Dash, as the Chairman of the Cuttack Gramya Bank, Cuttack, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-76/AC]

**का० आ० 1902.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर के अध्यक्ष के रूप में श्री बी० के० अश्वाल को नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 3-2/77-आर० आर० बी०]

**S.O. 1902.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri V. K. Agarwal as the Chairman of the Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank, Gorakhpur, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 3-2/77-RRB]

**का० आ० 1903.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा के अध्यक्ष के रूप में श्री पी० के० जैन की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-70/75-ए० सी०]

**S.O. 1903.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri P. K. Jain, as he Chairman of the Bhojpur Rohtas Gramin Bank, Arrah, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-70/75-AC]

**आ० आ० 1904.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा राय बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राय बरेली के अध्यक्ष के रूप में श्री बी० के० सिन्हा की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 3-15/77-आर० आर० बी०]

**S.O. 1904.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri B. K. Sinha, as the Chairman of the Rae Bareilly Kshetriya Baramin Bank, Rae Bareilly, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 3-15/77-RRB]

**का० आ० 1905.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर के अध्यक्ष के रूप में श्री टी० एम० राजासेखर की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 3-28/77-आर० आर० बी०]

**S.O. 1905.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri T. M. Rajasekhar, as the Chairman of the Cauvery Gramina Bank, Mysore, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 3-28/77-RRB]

**का० आ० 1906.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गुडगांव ग्रामीण बैंक, गुडगांव के अध्यक्ष के रूप में श्री आर० सी० बुद्धराज की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-85/75-ए० सी०]

**S.O. 1906.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri R. C. Budhiraja, as the Chairman of the Gurgaon Gramin Bank, Gurgaon, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-85/75-AC]

**का० आ० 1907.**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मराठवाडा ग्रामीण बैंक, नन्देड के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० के० फडनावीस की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 3-24/77-आर० आर० बी०]

**S.O. 1907.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 19th December, 1977 relating to the appointment of Shri S. K. Fadnavis as the Chairman of the Marathwada Gramin Bank, Nanded, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 3-24/77-RRB]

**क्र० आ० 1908**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा प्रथम बैंक, मुरावाबाद के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० आर० दस्तगीर की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के "30 जून, 1978" श्रंको, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "31 दिसम्बर, 1978" श्रंक, अक्षर और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एक० 4-15/75 ए० सी०]

**S.O. 1908.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri S. R. Dastgir, as the Chairman of the Prathama Bank, Moradabad, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978," the figures, letter and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-15/75-AC]

**क्र० आ० 1909**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा जयपुर-नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० एल० जैन की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के "30 जून, 1978" श्रंको, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "31 दिसम्बर, 1978" श्रंक, अक्षर और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एक० 4-12/75 ए० सी०]

**S.O. 1909.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri. S. L. Jain, as the Chairman of the Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank, Jaipur, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-12/75-AC]

**क्र० आ० 1910**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कूचबिहार के अध्यक्ष के रूप में श्री सिद्धेश्वर सेन शर्मा की नियुक्ति विषयक इस विभाग

की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के "30 जून, 1978" श्रंको, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "31 दिसम्बर, 1978" श्रंक, अक्षर और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एक० 4-141/76-ए० सी०]

**S.O. 1910.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri Siddeswar Sen Sarma, as the Chairman of Uttar Bonga Kshetriya Gramin Bank, Cooch-Bihar, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-141/76-AC]

**क्र० आ० 1911** प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गौड़ ग्रामीण बैंक, मालदा के अध्यक्ष के रूप में श्री बिमल चक्रवर्ती की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना के "30 जून, 1978" श्रंको, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "31 दिसम्बर, 1978" श्रंक, अक्षर और शब्दों प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एक० 4-141/75-ए० सी०]

एम० पी० वर्मा, अवर सचिव

**S.O. 1911.**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri Bimal Chakraborty as the Chairman of the Gaur Gramin Bank, Malda, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June 1978", the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-11/75-AC]

M. P. VARMA, Under Secy.

नई दिल्ली 15 जून 1978

**क्र० आ० 1912**—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री बी० के० शंग्लू के स्थान पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली के निदेशक श्री ग्रहण मिश्र को एतद्वारा सिन्डिकेट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एक० 9/16/78 बी०ओ०-1]

New Delhi, the 15th June, 1978

**S.O. 1912.**—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Arun Sinha, Director, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi as a Director of the Syndicate Bank, vice Shri V.K. Shunglu.

[No. F. 9/16/78-BO.I]

नई दिल्ली, 21 जून, 1978

क्र०आ० 1913.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19(2) के उपबंध 12 फरवरी, 1980 तक यूनियन बैंक आफ इंडिया पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहाँ तक वे बनारस स्टेट बैंक लि०, वाराणसी की इसकी शेषरधारिता से सम्बद्ध रखते हैं।

[संख्या एफ० 15(11) बीओ०III/78]

मे० आ० उसगांवकर, अवर सचिव

New Delhi, the 21st June, 1978

S.O. 1913.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 19(2) of the said Act shall not apply till 12th February 1980 to Union Bank of India in so far as they relate to its holdings in the shares of Benares State Bank Ltd., Varanasi.

[No. 15(11)-B.O. III/78]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जून, 1978

क्र०आ० 1914.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्वारा श्री बी० आर० देसाई को 1 अप्रैल, 1978 से प्रारम्भ होने वाली और 18 जून, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[सं० 9/2/78-बी०ओ०-(I)(1)]

New Delhi, the 16th June, 1978

S.O. 1914.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby reappoints Shri V.R. Desai and the Managing Director of the United Commercial Bank for a further period commencing on 1st April, 1978 and ending with 18th June, 1978.

[No. F. 9/2/78-BO.I(1)]

क्र०आ० 1915.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा श्री बी० आर० देसाई को, जिन्हें 1 अप्रैल, 1978 से यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 9/2/78-बी०ओ०-I(2)]

S.O. 1915.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India hereby appoints Shri V.R. Desai who has been reappointed as Managing Director of the United Commercial Bank with effect from 1st April, 1978 to be the Chairman of the Board of Directors of the United Commercial Bank with effect from the same date.

[No. F. 9/2/78-BO.I (2)]

क्र०आ० 1916.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा श्री बी०के० चटर्जी को 19 जून, 1978 से प्रारम्भ होने वाली और 18 जून, 1981 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 9/2/78-बी०ओ०-I(3)]

S.O. 1916.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri B.K. Chatterji, as the Managing Director of the United Commercial Bank for the period commencing on 19th June, 1978 and ending with 18th June, 1981.

[No. F. 9/2/78-BO. I (3)]

क्र०आ० 1917.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्वारा श्री बी०के० चटर्जी को, जिन्हें 19 जून, 1978 से यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के निवेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 9/2/78-बी०ओ०-I(4)]

बलदेव सिंह संयुक्त सचिव

S.O. 1917.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India hereby appoints Shri B.K. Chatterji, who has been appointed as Managing Director of the United Commercial Bank with effect from 19th June, 1978 to be the Chairman of the Board of Directors of the United Commercial Bank with effect from the same date.

[No. F. 9/2/78-BO. I (4)]

Baldev Singh: Jt. Secy.

### वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारीता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 जून, 1978

क्र०आ० 1918.—चाय नियम 1954 के नियम 4 तथा 5 के साथ पठित चाय अधिनियम 1953 (1953 का 29) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्रीमती जहानारा जयपाल सिंह के स्थान पर श्री जवाहरलाल बनर्जी को, जो राज्य सभा के सदस्य हैं, उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित चाय बोर्ड के सदस्य के रूप में 22 अगस्त 1978 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है एतद्वारा नियुक्त करती है और भारत सरकार के वाणिज्य

मन्त्रालय की अधिसूचना कां० प्रा० सं० 444(प्र) दिनांक 23 अगस्त, 1975 में निम्नोक्त और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में पहले स्तम्भ में मद सं० 9 के सामने प्रविष्टि के स्थान पर निम्नोक्त प्रविष्टि रखी जायेगी:—

“श्री जाह्न लाल बनर्जी

131, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-1

[सं० ई-12012(1)/74-प्लांट (ए)]

एस० महादेव अय्यर, उप निदेशक

## MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

### Department of Commerce

**S.O. 1918.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), read with rules 4 and 5 of the Tea Rules, 1954, the Central Government hereby appoints Shri Jaharlal Banerjee, member of Rajya Sabha, vice Shrimati Jahanara Jaipal Singh, as member of the Tea Board established under sub-section (1) of the said section upto, and inclusive of, the 22nd August, 1978, and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 444(E), dated the 23rd August, 1975, namely:—

In the said notification, for the entry in the first column against item number 9, the following entry shall be substituted, namely:—

“SHRI JAHARLAL BANERJEE, 131, North Avenue, New Delhi-1”.

[No. E-12012(1)/74-Plant(A)]

S. MAHADEVA IYER, Dy. Director

### मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

#### आवश

नई दिल्ली, 19 जून, 1978

कां० प्रा० 1919.—सर्वोच्च भारतीय उर्वरक निगम लि० (बरोनी एकक) पो० प्रा० बरोनी उर्वरक नगर (जिला बेगूसराय), बिहार कां० 4,05,398—रुपए (चार लाख पांच हजार तीन सौ अठानवे रुपए मात्र) मूल्य का आयात लाइसेंस सं० आई०टी० 2243580 पी/एक्स एक्स/63/एच 43-44 दिनांक 10-6-77 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थायी हो गई है। आगे यह कहा गया है कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति को किसी भी बैंक में पंजीकृत नहीं करवाया गया था। इसे शून्य रुपए के लिए उपयोग में लाया गया था और 14-6-78 को इसमें 4,05,398 रुपए जोड़ दिए।

2. अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक ने शपथ आयुक्त के प्रमाण पत्र के साथ एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

3. मैं तदनुसार संतुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई है। इसलिए यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आवेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की उपधारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, बरोनी को जारी किए गए उक्त लाइसेंस सं० आई०टी० 2243580 दिनांक 10-6-77 की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति एत द्वारा रद्द की जाती है।

4. उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं० फर्ट 41/76-77/पी एच एस(ए)/391]

एम० एल० भार्गव, उप-मुख्य नियंत्रक

## OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

### ORDER

New Delhi, the 19th June, 1978

**S.O. 1919.**—M/s. The Fertiliser Corporation of India Limited (Barauni Unit) P.O. Barauni Urvarak Nagar (Distt. Begu Sarai) Bihar, were granted an import licence No. I/D/2243580/P/XX/H/43-44/dated 10-6-77 for Rs. 4,05,398 (Rupees Four lakhs five thousand three hundred and ninety eight only) They have applied for the issue of a duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence on the ground that the Original Exchange Control purposes copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Exchange Purposes copy was not registered with any bank. It was utilised for Rs. Nil and the balance available on it was Rs. 4,05,398 as on 14-6-1978.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit along with a certificate from Oath Commissioner.

3. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-55 as amended the said original Exchange Control Purposes copy of licence No. I/D/2243580 dated 10-6-78 issued to M/s. The Fertiliser Corporation of India, Ltd., Barauni, is hereby cancelled.

3. A duplicate exchange control purposes copy of the said licence is being issued separately to the licensee.

[No. Fert/41/76-77/PLS(A)/391]

M. L. BHARGAVA, Dy. Chief Controller

### वाणिज्य, नागरिक पूत तथा सहकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जून, 1978

कां० प्रा० 1920.—केंद्रीय सरकार, सरकारी स्थान (प्रवाधिकृत अधिनियमों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, और आगे निदेश देती है कि उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत, अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

#### सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
उप विकास आयुक्त, (विकास), सांता क्रुज इलेक्ट्रानिक नियति प्रसंस्करण क्षेत्र (एस ई ई पी जेड), क्षेत्र (एस ई ई पी जेड) मुखर्ई, और सम्पदा प्रबन्धक, सांता क्रुज इलेक्ट्रानिक नियति प्रसंस्करण क्षेत्र मुखर्ई	सांता क्रुज इलेक्ट्रानिक नियति प्रसंस्करण क्षेत्र (एस ई ई पी जेड), मुखर्ई के, या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए स्टाफ क्वार्टर, मानक डिजाइन कारखाना भवन में निर्मित स्थान, भूमि (खुले प्लाट) और अन्य सम्पत्ति।

[कां० सं० 1(9)/77ई पी जेड]

सुदर्शन सिंह, उप निदेशक

New Delhi, the 20th June, 1978

**S.O. 1920.**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being gazetted officers of Government to be estate officers for the purposes of the said Act, and further directs that the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on the estate officers by or under the said Act, within the limits of their respective jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
1. Deputy Development Commissioner (Development) Santacruz Electronics Export Processing Zone (SEEPZ), Bombay	Staff Quarters, Built up space in Standard Design Factory Building, land (Open Plots), and other property belonging to or taken on lease by Santacruz Electronics Export Processing Zone (SEEPZ), Bombay.
2. Estate Manager, Santacruz Electronics Export Processing Zone, Bombay.	-do-

[F. No. 1(9)/77-EPZ]

SUDARSHAN SINGH, Dy. Director

नई दिल्ली, 1 जुलाई 1978

**क्रा० १० 1921.**—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सामान्य नमक का निर्यात (निरीक्षण)

नियम, 1977 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम प्रस्तावित है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामान्य नमक का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सामान्य नमक का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1977 में, नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“3. निरीक्षण का आधार:—सामान्य नमक का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के विचार से किया जाएगा कि उगकी क्वालिटी अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य तथा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 2190 तारीख 2 जुलाई, 1977 के साथ प्रकाशित, विनिर्देशों के अनुरूप है।”

[सं० 6(5)/75 नि०नि० तथा नि०उ०]

सी० बी० कुक्रेती, संयुक्त निदेशक

New Delhi, the 1st July, 1978

**S.O. 1921.**—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Common Salt (Inspection) Rules, 1977, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Export of Common Salt (Inspection) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Common Salt (Inspection) Rules, 1977, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

“3. Basis of Inspection—Inspection of Common Salt shall be carried out with a view to ensuring that the quality of the same conforms to the specifications as recognised by the Central Government under section 6 of the Act, and published with the order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2190, dated the 2nd July, 1977.”

[No. 6(5)/75-EI&amp;EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director.

## भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1978-06-15

**क्रा० आ० 1922.**—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन बिन्दु) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-5869 और 5870 जिसके व्योरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, फर्म का स्वामीत्व बचल जाने के कारण 1977-11-28 से रद्द कर दिया गया है।

## अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के व्योरे वस्तु/प्रक्रिया	तत्संबंधी भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	5869 1977-02-03	श्री रतन नरहरतन (प्रा) लि०, 156/बी सानिकनल्ला मेन रोड, कलकत्ता-700054 (पं० बंगाल) कार्यालय 115, केनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 (पं० बंगाल)	संरचना इस्पात (मानक किस्म)	IS : 226-1975 संरचना इस्पात (मानक किस्म) की विशिष्टि (पाँचवां पुनरीक्षण)

1	2	3	4	5
2.	5870 1977-02-03	-वही-	संरचना इस्पात (माध्यम किस्म)	IS : 1977-1975 संरचना इस्पात (माध्यम किस्म) की विशिष्ट (द्वारा पुनरीक्षण) [संख्या सीएमडी/55 : 5869]

वाई० एन० वेंकटेश्वरन, अतिरिक्त महानिदेशक

## INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, 1978-06-15

**S.O. 1922.**—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-5869 & 5870 particulars of which are given below have been cancelled with effect from 1977-11-28 due to change in the ownership of the firm.

## SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name & Address of the Licensee	Article/Process covered by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	5869 1977-02-03	Shreeratan Navratan (P) Ltd., 156/B, Manicktala Main Road, Calcutta-700054 (West Bengal) (Office : 115, Canning Street, Calcutta-700001 (West Bengal).	Structural Steel (Standard Quality)	IS : 226-1975 Specification for structural steel (standard quality)—(fifth revision)
2.	5870 1977-02-03	Do.	Structural Steel (Ordinary Quality)	IS : 1977-1975 Specification for structural steel (ordinary quality)—(Second revision).

[No. CMD/55 : 5869]

Y. S. VENKATESWARAN, Additional Director General

## ऊर्जा मंत्रालय

## (कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 1978

का०आ० 1923.—कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 36) की धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा एच०के० वर्मा को, 20 फरवरी, 1978 के पूर्वार्द्ध से सहायक भुगतान आयुक्त नियुक्त करती है।

[सं० 11024/9/78-सी०ए०]

जी० वी० जी० रामन, उप सचिव

## MINISTRY OF ENERGY

## (Department of Coal)

New Delhi, the 25th May, 1978

**S.O. 1923.**—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (2) of Section 20 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (36) of 1972, the Central Govt. hereby appoints Shri H. K. Verma, as Assistant Commissioner of Payments with effect from the fore-noon of the 20th February, 1978.

[No. 11024/9/78-CA]

G. V. G. RAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 15 जून, 1978

का०आ० 1924.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपान्वत अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयला प्रभिक्षण किये जाने की संभावना है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जेंट और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसमें कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक और निरीक्षण सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) कार्यालय, दरभंगा हाउस, रांची या उपायुक्त का कार्यालय, पलामू (डाल्टनगंज) जिला, या कोयला नियंत्रक का कार्यालय, 1 काउन्सिल हाउस, कलकत्ता में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में हितवाञ्छी सभी व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में वर्णित सभी नक्शे, चार्ट और अन्य दस्तावेजों इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर राजस्व अधिकारी, केन्द्रीय कोल फील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची के पास भेजना चाहिए।

ड्राइंग सं० राजस्व/5/78 तारीख 6-2-78

(पूर्वक्षेत्र के लिए अधिसूचित क्षेत्र)

अनुसूची

दक्षिणी धाधु अंचल

उत्तरी कर्णपुरा, कोयला क्षेत्र (बिहार)

क्र० सं०	ग्राम	थाना सं०	अंचल	जिला	क्षेत्रफल	टिप्पणी
1.	चित्तपुर	210	बालूमठ	पलामू	भाग	
2.	धाधु	212	"	"	"	
3.	चकला	238	चन्दवा	"	"	
4.	महुआमिलन	279	"	"	"	
5.	जमीरा	281	"	"	"	
6.	अरधे	282	"	"	"	
7.	देवनदिया	298	"	"	"	

कुल क्षेत्रफल : 6945 एकड़ (लगभग) या  
2810.10 हेक्टेयर (लगभग)

क-ख-ग-घ-ङ रेखाएं बालूमठ, अंचल के चित्तपुर ग्राम और चन्दवा अंचल के चकला, महुआमिलन और अरधे ग्रामों में से होकर गुजरती है।

इ-ए-छ-ज-झ रेखाएं चन्दवा अंचल के अरधे, जमीरा, महुआमिलन और देवनदिया ग्रामों से होकर गुजरती है।

झ-ञ रेखा, चन्दवा अंचल के देवनदिया और मल्हन ग्रामों की प्रांशिक सामान्य सीमा के साथ साथ चलती है।

अ-ट-ठ-ड-ढ-ण रेखाएं, चन्दवा अंचल के देवनदिया, महुआमिलन, चकला और बालूमठ अंचल के धाधुआ और चित्तपुर ग्रामों से होकर गुजरती है।

ण-क रेखा चन्दवा अंचल के चित्तपुर ग्राम में से होकर गुजरती है और प्रारंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[सं० 19(12)/78-सी एल]

एस० आर० ए० रिज्मी, निदेशक

New Delhi, the 15th June, 1978

**S.O. 1924.**— Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi or at the office of the Deputy Commissioner, Palamau, Daltanganj (Bihar) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi within 90 days from the date of publication of this notification.

DRG. No. Rev/5/78

Dated 6-2-78

(AREA NOTIFIED FOR PROSPECTING)

SCHEDULE

SOUTH DHADHU BLOCK  
NORTH KARANPURA COALFIELD (BIHAR).

Sl. No.	Village	Thana	Thana No.	Anchal	District	Area	Remarks
1.	Chitarpur	Balumath	210	Balumath	Palamau		Part
2.	Dhadhu	"	212	"	"		"
3.	Chakla	"	238	Chandwa	"		"
4.	Mahuamilan	"	279	"	"		"
5.	Zamira	"	281	"	"		"
6.	Ardhe	"	282	"	"		"
7.	Deonadia	"	298	"	"		"

Total area:— 6945.00 acres (approximately)  
or 2810.10 hectares (approximately)

A-B-C-D-E	Lines pass through villages Chitarpur of Balumath Anchal and through villages Chakla, Mahuamilan and Ardhe of Chandwa Anchal.
E-F-G-H-I	Lines pass through village Ardhe, Zamira, Mahuamilan and Deonadia of Chandwa Anchal.
I-J	Line passes along the part common boundary of villages Deonadia and Malhan of Chandwa Anchal.
J-K-L-M-N-O	Lines pass through villages Deonadia, Mahuamilan, Chakla of Chandwa Anchal and through villages Dhadhu and Chitarpur of Balumath Anchal.
O-A	Line passes through village Chitarpur of Chandwa Anchal and meets at starting point 'A'.

[No. 19(12)/78-CL.]

S. R. A. RIZVI, Director



## पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 9 जून, 1978

का० आ० 1925.—भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहाँ संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के मेहसाना तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधान स्थल सं० एन० के० वी० एम० से एम० पी० ई० तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 12-6-1977 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्-द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

## अनुसूची

एन० के० वी० एम० से एम० पी० ई० तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का० आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	भटारीया	612	4-3-1978	12-6-1977

[सं० 12016/3/78-प्रो०-I]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS &amp; FERTILIZER

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 9th June, 1978

S.O. 1925.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. Well No. NKBM to SPE in Mehsana oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil and Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 12-6-77.

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipe-lines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

293 GI/78—3

## SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. Well No. NKBM to SPE

Name of Ministry	Villages	S.O.No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
1	2	3	4	5
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Bhatariya	612	4-3-78	12-6-77

[No. 12016/3/78-Prod.-I]

का० आ० 1926.—भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहाँ संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खंड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वेधान स्थल सं० एस एन के-8 से एस एन के-1 तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 28-6-77 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्-द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति तिथि अधिसूचित करते हैं।

## अनुसूची

एस एन के-8 से एस एन के-1 तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का० आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	रोहिद	438	18-2-78	28-6-77

[सं० 12016/3/78-प्रो०-II]

S.O. 1926.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. SNK-8 to SNK-1 in Ankleshwar oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (1) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 28-6-77.

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipe-lines (Acquisition of Right of User on Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

## SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline From D.S. SNK-8 to SNK-1

Name of Ministry	Villages	S.O.No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
1	2	3	4	5
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Rohid	438	18-2-78	28-6-77

[No. 12016/3/78-Prod.-II]

का०आ० 1927.—भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के मेहसाना तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में खेदान स्थल सं० एस पी एच (ए) से एन के वी तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उप-खण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य विनांक 19-11-76 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

## अनुसूची

एस पी एच (ए) से एन के वी तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	भटारिया और ममेदपुरा	433	18-2-78	19-11-76

[सं० 12016/3/78-प्रो०-III]

S.O 1927.—Whereas by the notification of Government of India as shown in schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. SPH (A) to NKV in Mehsana oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 19-11-76.

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

## SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline From D. S.PH (A) to NKV

Name of Ministry	Villages	S.O.No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
1	2	3	4	5
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Bhatariya & Memadpura	433	18-2-78	19-11-76

[No. 12016/3/78-Prod.-III]

का० आ० 1928.—भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में खेदान स्थल सं० 209 (अंकलेश्वर-5) से जी० जी० एस-III तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य विनांक 30-3-77 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

## अनुसूची

209 (अंकलेश्वर-5) से जी० जी० एस-III तक पाइप लाइन कार्य को समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	अंकोल	3545	19-11-77	30-3-77

[सं० 12016/3/78-प्रो०-IV]

जी० के० दुदाणी, गुजरात के लिए नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

S.O. 1920.—Whereas by the notification of Government of India as shown in schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. 209 (ANK-5) to GGS-III in Ankleshwar oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 30-3-77.

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

#### SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline From D.S. 209 (ANK-5) to GGS-III

Name of Ministry	Villages	S.O.No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
1	2	3	4	5
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Adol	3545	19-11-77	30-3-77

[No. 12016/3/78-Prod-IV]

G.K. DUDANI, Competent Authority Under the Act for Gujarat

#### नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 17 जून, 1978

कां.आ. 1929.—मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 117 के नीचे स्पष्टीकरण के उपबन्धों के अनुसरण में और नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की दिनांक 22-2-78 की अधिसूचना सं. सां.आ. 124 (ई) का प्रतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित औषधियों को ऐसी औषधियाँ निर्दिष्ट करती है जिनके सेवन से कोई व्यक्ति किसी मोटर गाड़ी पर ठीक नियंत्रण रखने में असमर्थ हो जाता है।

#### 1. केन्द्रीय नर्वस सिस्टम डेप्रेसन्ट :

- (क) कशाश्रिया
- (ख) कोफाइन

#### 2. हिप्नोटिक्स सोडाटिक्स :

- (क) ऐलोबारबिटोन
- (ख) फानोबारबिटल
- (ग) सीकोबारबिटल
- (घ) सार्बिसोबारबिटोन
- (ङ) बार्बिटोन
- (च) मेथा कोलीम
- (छ) क्लोरल हाइड्रेट

#### 3. नार्कोटिक एनलाजीसेज :

- (क) मोर्फिन
- (ख) पेथाडीन

#### 4. सार्कोट्रापिक औषधियाँ :

लिसजिक एसिड डि-इथीलराईड (एल०एस०डी०)

#### 5. उत्तेजक पदार्थ :

- (क) एनफेडामिन
- (ख) मेथाईल कनीडेड हाईड्रोक्लोराईड

#### 6. प्रशान्तक :

- (क) डायजिपम
- (ख) क्लोराईडिआरोफोक्साईड
- (ग) नाइट्रोजेपम

[टी० जी० एम० (5)/78]

एन०ए०ए० नारायणन, उप सचिव

#### MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 17th June, 1978

S.O. 1929.—In pursuance of the provisions of the Explanation below section 117 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), and in supersession of the Notification of the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 124 (E) dated the 22nd February, 1978, the Central Government hereby specifies the following drugs which shall be deemed to render a person incapable of exercising proper control over a motor vehicle namely :—

#### 1. Central Nervous System Depressant :

- (a) Cannabina.
- (b) Cocaine.

#### 2. Hypnotics Sedatives :

- (a) Allobarbitone.
- (b) Phenobarbital.
- (c) Secobarbital.
- (d) Cyclobarbitone.
- (e) Barbitone.
- (f) Methaqualone.
- (g) Chloral Hydrate.

#### 3. Narcotic Analgesics :

- (a) Morphine.
- (b) Pethidine.

#### 4. Psycho-tropic drugs :

Lysergie Acid Di-ethylamide (L.S.D.).

#### 5. Stimulants :

- (a) Amphetamin.
- (b) Methyl Phenidate Hydrochloride.

#### 6. Tranquilizers :

- (a) Diazepam.
- (b) Chloridiazepoxide.
- (c) Nitrazepam.

[No. TGM(S)/78]

N. A. A. NARAYANAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 जून, 1978

का० प्रा० 1930.—दिल्ली परिवहन (सलाहकार परिषद्) नियम-1973 के नियम 3 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित दिल्ली परिवहन निगम के विचार आने के बाद, एतद्वारा श्री शिव नारायण सरसोनिया, सदस्य, लोक सभा, नयी दिल्ली, निवास 4757/46, रेगड़पुरा, करोल बाग नयी दिल्ली-5 को उक्त नियमों के नियम 6, 7, 8, और 22 में निर्दिष्ट शर्तों पर श्री कंवर लाल गुप्ता के स्थान पर, उक्त नियमों के नियम 11 में निर्दिष्ट मामलों पर उक्त निगम के सलाह देने के लिए पठित दिल्ली परिवहन निगम सलाहकार परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है, और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की 31-12-1977 की अधिसूचना सं० सा० प्रा० 870(ई) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में पैरा 1 में, मंत्र 5 की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "श्री शिव नारायण सरसोनिया, सदस्य, लोक सभा, नयी दिल्ली" प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा० सं० टी० जी० डी० (166)/76]

एन० ए० ए० नारायणन, उप सचिव

New Delhi, the 20th June, 1978

S.O. 1930.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), read with rule 3 of the Delhi Transport (Advisory Council) Rules, 1973, the Central Government, after ascertaining the views of the Delhi Transport Corporation, established under section 3 of the said Act, hereby appoints Shri Shiv Narain Sarsonia, Member, Lok Sabha, New Delhi, resident of 4757/46 Raigarh, Karolbagh, New Delhi-5 as a member of the Delhi Transport Corporation Advisory Council constituted for the purpose of advising the said Corporation on the matters specified in rule 11 of the said rules vice Shri Kanwar Lal Gupta, on the terms specified in rules 6, 7, 8 and 22 of the said rules and makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. S.O. 870(E), dated the 31st December, 1977, namely :—

In the said notification, in paragraph 1, for the entry against item (5), the entry, "Shri Shiv Narain Sarsonia, Member, Lok Sabha, New Delhi" shall be substituted.

[F. No. TGD(166)/76]

N. A. A. NARAYANAN, Dy. Secy.

## परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई, 26 मई, 1978

का० प्रा० 1931.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 1410, तारीख 25 फरवरी, 1977 को अधिस्तान करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी को, जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करता है, और उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत उक्त अधिनियम के द्वारा या अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

## सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थान
1	2
प्रबन्धक (कामिक तथा प्रशासन) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, डाकघर जादूगुडा माईंस, जिला सिहभूम, बिहार।	यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, डाकघर जादूगुडा माईंस, जिला सिहभूम, बिहार के 51 उसके लिए पट्टे पर लिए गए परिसर जो उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं।

[फा० सं० 13/2/73-एच]

एल० एच० मीरचन्दानी, उप सचिव

## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay the 18th May, 1978

S.O. 1931.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants), Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Atomic Energy No. S. O. 1410 dated the 25th February 1977, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in Column (1) of the Table below, being a gazetted officer of Government, to be the Estate Officer for the purposes of the said Act, and the said officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

## TABLE

Designation of the officer	Public Premises
(1)	(2)
Manager (Personnel and Administration) Uranium Corporation of India Ltd., Post Office Jaduguda Mines, District Singhbhum, Bihar.	Premises belonging to or taken on lease for the Uranium Corporation of India Ltd. Post Office Jaduguda Mines, District, Singhbhum Bihar and which are under its administrative control.

[F. No. 13/2/73-(H)]

L. H. MIRCHANDANI, Dy. Secy.

## स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 15 जून, 1978

का० प्रा० 1932.—यतः भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की 15 जून, 1978, की अधिसूचना संख्या बी० 11016/14/78-एम. ई./पी.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद्

अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए "एम.बी.बी.एस. (यूनिवर्सिटी आफ मरबर्ग, पश्चिम जर्मनी)", की चिकित्सा ग्रहता मान्य चिकित्सा ग्रहता होगी;

और यतः डा. हिल्डेगार्ड लूसी एडेलहीड बोविंग जिनके पास उक्त ग्रहता है फिलहाल साल्वेशन आर्मी कैथरिन बूथ हास्पीटल, नागेरकोयल, तमिलनाडु के साथ संबंध हैं;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा—

(1) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्ष की; अवधि

(2) उस अवधि को जब तक डा. हिल्डेगार्ड लूसी एडेलहीड बोविंग उक्त साल्वेशन आर्मी कैथरिन बूथ हास्पीटल, नागेरकोयल, तमिलनाडु के साथ संबंध रहते हैं जो भी कम हो वह अवधि विनिश्चित करती है, जिसमें पूर्वोक्त डाक्टर मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे।

[संख्या बी० 11016/14/78-एम.ई. (पी०)]

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

### ORDER

New Delhi, the 15th June, 1978

**S.O. 1932.**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Health No. V. 11016/14/78-M.E.(Policy) dated the 15th June, 1978, the Central Government has directed that the Medical qualifications, "M.B.B.S. (University of Marburg, West Germany)", shall be a recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. Hildegard Lusie Adelheid Boving who possesses the said qualification is for the time-being attached to the Salvation Army Catherine Booth Hospital, Nagercoil, Tamilnadu.

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (I) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a further period of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette, or

(ii) the period during which Dr. Hildegard Lusie Adelheid Boving is attached to the said Salvation Army Catherine Booth Hospital, Nagercoil, Tamil Nadu.

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/14/78-M.E. (Policy)]

आदेश

**का०आ० 1933.**—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 30 दिसम्बर, 1960 की अधिसूचना सं० 17-59/59-एम-1 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा यूनिवर्सिटी, यू०एस०ए० द्वारा प्रदत्त एम०डी० चिकित्सा ग्रहता मान्य चिकित्सा ग्रहता होगी;

और यतः डा० एडवर्ड बी० क्रोवेल जिनके पास उक्त ग्रहता है शैक्षिक और अनुसंधान कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल क्रिश्चियन मेडिकल कालेज और ब्राउन मेमोरियल अस्पताल, लुधियाना, पंजाब के साथ सम्बद्ध हैं;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा—

(1) 30 सितम्बर, 1978 तक की अवधि, अवधि

(2) उस अवधि को जब तक डा० एडवर्ड बी० क्रोवेल क्रिश्चियन मेडिकल कालेज और ब्राउन मेमोरियल अस्पताल, लुधियाना, पंजाब के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो वह अवधि विनिश्चित करती है, जिसमें पूर्वोक्त डाक्टर उक्त संस्थान में मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे।

[सं० बी० 11016/11/78-एम० ई० (पी०)]

### ORDER

**S.O. 1933.**—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 17-59/59-MI. dated the 30th December, 1960, the Central Government has directed that the Medical qualification "M.D., awarded by Chicago University, U.S.A." shall be recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. Edward B. Crowell, who possesses the said qualification is for the time-being attached to the Christian Medical College and Brown Memorial Hospital, Ludhiana, Punjab for the purposes of teaching and research;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (I) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a further period upto 30th September, 1978, or

(ii) the period during which Dr. Edward B. Crowell is attached to the said Christian Medical College and Brown Memorial Hospital, Ludhiana, Punjab,

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited to the said institution.

[No. V. 11016/11/78-M.E.(POLICY)]

आदेश

**का०आ० 1934.**—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 23 जुलाई, 1962 की अधिसूचना सं० 16-5-62-एम-1 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए यूनिवर्सिटी आफ जार्ज टाउन, वाशिंगटन, यू०एस०ए० द्वारा प्रदत्त एम०डी० चिकित्सा ग्रहता मान्य चिकित्सा ग्रहता होगी;

और यतः डा० इलीन नीडफील्ड जिनके पास उक्त ग्रहता है फिलहाल होसी पैमिली अस्पताल मंडर, रांची के साथ सम्बद्ध हैं;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा—

(1) 31-12-1978 तक की अवधि, अवधि

(2) उस अवधि को जब तक डा० इलीन नीडफील्ड होसी पैमिली अस्पताल मंडर रांची के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो वह अवधि विनिश्चित करती है, जिसमें पूर्वोक्त डाक्टर मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे।

[सं० बी० 11016/12/78-एम०ई० (पी०)]

**S.O. 1934.**—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. F. 16-5/62-MI dated the 23rd July, 1962 the Central Government has directed that the Medical qualification, M. D. awarded by the University of Georgetown Washington, U.S.A., shall be

recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. Eileen Niedfield who possesses the said qualification is for the time being attached to the Holy Family Hospital, Mandar, Ranchi.

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

- (i) a period upto 31-12-78, or
- (ii) the period during which Dr. Eileen Niedfield is attached to the said Holy Family Hospital, Mandar Ranchi,

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited,

[No. V. 11016/12/76-M.E.(Policy)]

नई दिल्ली, 16 जून, 1978

आवेश

कांआं 1935.—यतः भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की 16 जून, 1978, की अधिसूचना संख्या बी० 11016/34/77-एम०पी०टी०/एम०ई० (पी०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए "एम०बी०बी०एस० (मुनिस्मिटी आफ न्यू साउथ वेल्स, आस्ट्रेलिया)" की चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी;

और यतः डा० जान रिचार्ड जिसके पास उक्त अर्हता है, फिलहाल चर्च आफ साउथ इंडिया हास्पिटल, बंगलौर के साथ सम्बद्ध है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा—

- (1) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्ष की, अवधि
- (2) उस अवधि को जब तक डा० जान रिचार्ड उक्त चर्च आफ साउथ इंडिया हास्पिटल, बंगलौर के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है जिसमें पूर्वोक्त डाक्टर मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे।

[सं० बी० 11016/34/77-एम० पी० टी०/एम० ई० (पी०)]

#### ORDER

New Delhi, the 16th June, 1978

**S.O. 1935.**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Health No. V. 11016/34/77MPT/ME(P) dated the 16th June, 1978, the Central Government has directed that the Medical qualifications, "M.B.B.S. (University of New South Wales, Australia)" shall be a recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. John Richard who possesses the said qualification is for the time being attached to the Church of South India Hospital, Bangalore;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

- (i) a further period of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette, or
- (ii) the period during which Dr. John Richard is attached to the said Church of South India Hospital, Bangalore.

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/34/77-MPT/ME(P)]

कांआं 1936.—भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 14 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् इसके द्वारा निदेश करती है कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "एम०बी०बी०एस० (मुनिस्मिटी आफ न्यू साउथ वेल्स, आस्ट्रेलिया)" की चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी।

[सं० बी० 11016/34/77-एम०पी०टी०/एम०ई० (पी०)]

**S.O. 1936.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consultation with the Medical Council of India, hereby directs that the Medical Qualification "M.B.B.S. (University of New South Wales, Australia)" shall be recognised medical qualification for the purposes of that Act.

[No. V. 11016/34/77-MPT/ME(P)]

आवेश

नई दिल्ली, 17 जून, 1978

कांआं 1937.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 30 दिसम्बर, 1960 की अधिसूचना सं० ए० 16-18/60-एम० 1 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए "एम० डी० (मनस्टर) की चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा अर्हता होगी;

और यतः डा० आगस्ट ओटो बेने जिसके पास उक्त अर्हता है वैज्ञानिक अनुसंधान और धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए किरुक्कुली, त्रिचूर-5 संस्थान, कोझुकुली, त्रिचूर-5 के साथ सम्बद्ध है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा—

- (1) सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की

अवधि

- (2) उस अवधि को जब तक डा० आगस्ट ओटो बेने उक्त डेमियर (कुष्ठ) संस्थान, कोझुकुली, त्रिचूर-5 के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा० मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे।

[सं० बी० 11016/13/78-एम० ई० (पी०)]

आर० बी० ओतिनाथन्, उ० सचिव

#### ORDER

Delhi, the 17th June, 1978

**S.O. 1937.**—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. P. 16-18/60-M1, dated the 30th December, 1960, the Central Government has directed that the Medical qualification, "M.D. (Munster)" shall be recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas, Dr. August Oto Beine who possesses the said qualification is for the time being attached to the Damien Leprosy Institute, Kozhukully, Trichur-5, for the purposes of teaching, research and charitable work.

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies :—

- (i) a further period of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette, or

- (ii) the period during which Dr. August Beine is attached to the said Damien (Leprosy) Institute, Kozhukully, Trichur-5,

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/13/78-M.E. (Policy)]

R. V. SRINIVASAN, Dy. Secy.

### (स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 जून, 1978

का० आ० 1938.—वनः भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 20 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) के अनुसरण में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने डा० आर० के० बेमार्ड, जिनकी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की सदस्यता समाप्त हो गई है, के स्थान पर मेडिकल कॉलेज, त्रिवेन्द्रम के कान, नाक, गला के प्रोफेसर डा० पी० सुकुमारन को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति का सदस्य निर्वाचित किया है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा के साथ पठित उपधारा (1) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की 22 मई, 1975 की अधिसूचना संख्या बी 11019/1/75-एम पी टी में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में “भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्वाचित” शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:—

- “2. डॉ० पी० सुकुमारन,  
प्रोफेसर, नाक, कान गला,  
मेडिकल कॉलेज,  
त्रिवेन्द्रम”

[सं० बी० 11019/1/78-एम० ई० (पी)]

आर० वी० श्रीनिवासन, उप सचिव

(Department of Health)

New Delhi, the 19th June, 1978

S.O. 1938.—Whereas in pursuance of sub-section (1) read with sub-section (3) of section 20 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India has elected Dr. P. Sukumaran, Professor of E.N.T., Medical College, Trivandrum, to be a member of the Post-graduate Medical Education Committee vice Dr. R. K. Desai, who has ceased to be a member of the Medical Council of India, New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) read with sub-section (3) of section 20 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health and Family Planning No. V. 11019/1/75-MPT, dated the 22nd May, 1975, namely:—

In the said notification, under the heading “Elected by the Medical Council of India”, for serial No. 2 and the existing entry relating thereto, the following serial No. and entry shall be substituted, namely:—

- “2. Dr. P. Sukumaran,  
Professor of E.N.T., Medical College,  
Trivandrum.”

[No. V. 11019/1/78-M.E. (Policy)]

R. V. SRINIVASAN, Dy. Secy.

### निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जून, 1978

का० आ० 1939.—राष्ट्रपति, मूल नियमों के नियम 45 के उपबन्धों के अनुसरण में, सरकारी निवास-स्थान आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी निवास-स्थान आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) तृतीय संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी निवास स्थान आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम, 1963 में, अनुसूचक नियम 317-ख-15 के उपनियम (3) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु अधिवर्षिता की तारीख से ठीक छः मास पहले की अवधि के दौरान निवास के परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।”

[का० सं० 12033(1)/78-नीति II]

आर० डी० भाटिया, सम्पदा उप-निदेशक  
(नीति और प्रणामन)

### MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 17th June, 1978.

S.O. 1939.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi), Rules, 1963 namely:—

1. (1) These rules may be called the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Third Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, in sub-rule (3) of Supplementary Rule 317-B-15, the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

“Provided that no change of residence shall be allowed during a period of six months immediately preceeding the date of superannuation.”

[File No. 12033(1)/78-Pol.II]

R. D. BHATIA, Dy. Director of Estates

(Policy & Administration).

### दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1978

का० आ० 1940.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है जिसे सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है। इस संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस आपत्ति के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, पौषवी मंजिल, विकास मीनार, इन्दिरा प्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें। जो व्यक्ति

अपनी आपत्ति या सुझाव दें वे अपना नाम एवं पूरा पता भी लिखें।  
संशोधन :—

“लगभग 5.02 है० (12.4 एकड़) का क्षेत्र जो जौन सी-14 में चन्द्रावल वाटर वर्क्स के उत्तर में, माल रोड एक्सटेंशन के साथ राष्ट्रीय उच्च मार्ग वाई पास सं०-2 के बौराहे पर स्थित है और जो पूर्व में 91.5 मी० (300') चौड़े राष्ट्रीय उच्च मार्ग वाई पास सं०-2, दक्षिण में 61 मी० (200') माल रोड एक्सटेंशन तथा पश्चिम व उत्तर में मुख्य योजनानुसार मनोरंजन क्षेत्र (जिला उद्यान खेल के मैदान तथा खुले स्थानों) द्वारा घिरा हुआ है। इसे अब “मनोरंजन उपयोग” (जिला उद्यान खेल के मैदान एवं खुले स्थानों) से “घावासीय उपयोग” में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।”

2. प्रस्तावित संशोधन के मानचित्र का निरीक्षण शनिवार को छोड़ कर अन्य सभी कार्यशील दिनों में विल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय दसवीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त प्रबंध में किया जा सकता है।

[सं०-एफ-3(298)/65-एम० पी०]

कृष्ण प्रताप, सचिव

### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

#### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st July, 1978

**S.O. 1940.**—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 5th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address.

#### MODIFICATION :

“An area, measuring about 5.02 hecets. (12.4 acres) falling in zone C-14, in the north of Chandrawal Water Works, at the junction of National Highway By-pass No. II with Mall Road Extension, bounded by 91.5 mts. (300 ft.) National Highway By-pass No. II in the east 61 mts. (200 ft.) Mall Road Extension in the South and the Matter Plan Recreational area (District Parks, play-ground and open spaces) in the West and north, is proposed to be changed from “Recreational use” (District parks, playgrounds and Open spaces) to “Residential” use.”

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 3(298)/65-M.P.]

KRISHANA PRATAP, Secy.

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1978

**क्रा० प्रा० 1941.**—दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, 1957 (1957 की सं० 61) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि० वि० प्रा० एतद्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्ण-अनुमति से होटल्स, बोर्डिंग हाऊसिंग, गेस्ट हाऊसेज, होस्टल्स, लाजिंग

हाऊसिंग तथा मोटल्स (भवन स्तर) विनियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करना है :—

संशोधन :—

(1) नियम 1(4) निम्न प्रकार रखा जाता है :—

“इन नियमों के अधिप्राय के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय सरकार द्वारा किया जावेगा।”

(2) “सार्वजनिक संस्थानों और निजी कंपनियों” को नियम, 2(6) में दिये “अथवा सार्वजनिक संस्थानों” के स्थान पर रखा जाता है।

(3) “भूमि तल एवं प्रथम मंजिलों में 30 प्रतिशत तथा शेष मंजिलों” को नियम 3(2) (ए)(2) में दिये गये “प्रति मंजिल” के स्थान पर रखा जाता है।

(4) नियम 3(2)(ए)(6) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द होंगे :—

“5 स्टार होटल के लिये पार्किंग स्तर हेतु भवन/तहखाने के कटिलज के भीतर निर्मित स्थान के प्रत्येक 92.9 वर्ग मीटर (1000 वर्ग फुट) में 1.14 कारों का स्थान और अतिरिक्त पार्किंग जहां आवश्यक हो निर्मित स्थान के प्रत्येक 92.9 वर्ग मीटर (1000 वर्ग फुट) 1.14 कारों के स्थान तक सीमित बशर्ते कि भवन के घास-पास 50 प्रतिशत खुला स्थान हरित/भूदृश्य के लिये अवश्य छोड़ा जाये।

पार्किंग रेस्टोरेट, बैंक तथा अन्य संबन्धित सुविधाओं जिनमें सरकुलेशन हेतु क्षेत्र, रसोई, स्टोरेज तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं के उपयोग हेतु न्यूनतम भूतल क्षेत्र का 1.95 प्रति 92.90 वर्ग मीटर (1000 वर्ग फुट) के हिसाब से कार के स्थान के बराबर पार्किंग हो, तथा न्यूनतम 0.85 प्रति 92.90 वर्ग मीटर (1000 वर्ग फुट) के हिसाब से कार के स्थान के बराबर पार्किंग, शेष होटल के लिये है। (इसमें वहां कमी की जा सकती है जहां सार्वजनिक पार्किंग हो तथा जिसको होटल द्वारा उपयोग में लाया जाता है तथापि इसकी सीमा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई हो।”

(5) “कुल क्षेत्र में 33.45 वर्ग मीटर (400 वर्ग गज) तथा यह न्यूनतम 18.288 मी० (60') चौड़ी सड़क पर स्थित हो” को नियम 4(1) (सी) में आये “कुल क्षेत्र में 1005 वर्ग मीटर (1200 वर्ग गज)” के स्थान पर रखा जाता है।

(6) नियम 5(1) में आये “जैसा भी विषय हो” के स्थान पर “विशेष अपील के पश्चात् यदि प्राधिकरण द्वारा अनुमति की गई हो” शब्द रखे जाते हैं।

(7) नियम 5(2)(1) को निम्न प्रकार रखा जाता है :—

“(1) कुल क्षेत्र में से भूखण्ड का आधार 334.45 वर्ग मी० (400 वर्ग गज) से कम नहीं होगा किन्तु यह न्यूनतम 18.288 मी० (60') चौड़ी सड़क पर स्थित हो।”

[सं० एफ० 1(17)/74-एम० पी०]

कृष्ण प्रताप, सचिव

New Delhi, the 1st July, 1978

**S.O. 1941.**—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government hereby makes the following amendments to the Hotels, Boarding



Houses, Guest Houses, Hostels, Lodging Houses and Motels (Building Standards) Regulations, 1977 :—

#### AMENDMENTS :

- (1) Regulation 1(4) is substituted by the following words :—

"If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be decided by the Government".

- (2) The words :—"The Public Undertakings and Private Companies" are substituted for the words "or Public Undertakings" appearing in Regulation 2(6).

- (3) The words :—"On Ground and First Floors shall be 30 percent and on remaining floors" are substituted for the words "per floor" appearing in regulation 3(2) (a) (ii).

- (4) Regulation 3(2) (a) (vi)—is substituted by the following words :—

"Parking Standard for a 5 Star Hotel :—1.14 Car spaces per 92.9 square metres (1000 square feet) of built up space within the curtilage of the building/basement, and an additional parking, where required, limited to the extent of 1.1 car spaces per 92.9 square metres (1000 sq. feet) of the built up space, subject to the condition that 50 percent of the open space around the building should in any case, be left for greenery/landscaping.

Parking Standard for other hotels at an equivalent car space of at least 1.95 per 92.90 square metres (1000 square feet) of floor area for uses like shopping, restaurants, banqueting and convention facilities inclusive of areas for circulation, kitchens, storage and the like; and parking at an equivalent car space of at least 0.85 per 92.90 square metres (1000 square feet) of floor area for the rest of the Hotel. (This can be reduced where a public form of pooled parking exists to be availed of by the Hotel and if the extent of this is determined by the Authority)".

- (5) The words :—"334.45 square metres (400 square yards) in net area and is located on a minimum 18.288 metres (60 feet) wide road" are substituted for the words "1005 sq. metres (1200 sq. yds.) in net area", appearing in Regulation 4(1) (c).

- (6) The words :—"If allowed by the Authority after a special appeal" are substituted for the words "as the case may be" appearing in Regulation 5(1).

- (7) Regulation 5(2) (i) is substituted by the following words :—

"(i) plots shall not be less than 334.45 square metres (400 square yards) in net area and is located on a minimum 18.288 metres (60 feet) wide road".

[No. F. 1(17)/74-MP]

KRISHNA PRATAP, Secy.

#### भ्रम मंत्रालय

प्रदेश

नई दिल्ली, 3 जून 1978

का० आ० 1942:—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, येलेण्डु कोलियरीज, खम्मम जिला, आन्ध्र प्रदेश के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

293 GI/78—4

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

धनः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री के० पी० नारायण राव होंगे जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

#### अनुसूची

क्या सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र का श्री गजुला रामैया, शाटफायर, नं० 21 इन्क्लाइन, येलेण्डु कोलियरीज को 2 जुलाई, 1977 से सेवा-निवृत्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है, यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुसूची का हकदार है ?

[संख्या एल-21012/2/77-डिस्क-4(बी)]

भूपेन्द्र नाथ, डेस्क अधिकारी

#### MINISTRY OF LABOUR

#### ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1978

SO. 1942.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relating to the management of Singareni Collieries Company Limited, Yallandu Collieries, Khammam Distt. Andhra Pradesh and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (I) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri K. P. Narayana Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

#### THE SCHEDULE

Whether the action of the management of Singareni Collieries Co. Ltd., in retiring Shri Jajula Ramaiah, Shot firer, No. 21 Incline, Yellandu Collieries with effect from 2-7-77 is justified. If not, to what relief is the concerned workman entitled.

[No. L-21012(2)/77-D-IV(B)]

BHUPENDRA NATH, Desk Officer

नई दिल्ली, 15 जून, 1978

का० आ० 1943:—हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री एस० एम० कंवर के स्थान पर श्री ए० एन० विश्वार्थी, सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के भ्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1517, तारीख 14 अप्रैल, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 13 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"श्री ए० एन० विद्यार्थी  
सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,  
श्रम और रोजगार विभाग,  
सिमला"

[सं० यू० 16012(15)/76-एच० आई०]

New Delhi, the 15th June, 1978

**S.O. 1943.**—Whereas the State Government of Himachal Pradesh has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri A.N. Vidyarthi, Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Simla, to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri S. M. Kanwar.

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1517, dated the 14th April, 1976 namely :

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)", for the entry against item 13, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri A. N. Vidyarthi,  
Secretary to the Government of Himachal Pradesh,  
Labour and Employment Department,  
Simla."

[No. U-16012/15/76-HI]

नई दिल्ली, 17 जून, 1978

का० प्रा० 1944.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976, के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में कर्मचारी राज्य बीमा नियम, जो श्रम मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, के निम्नलिखित कार्यालयों के नाम उक्त उपनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचित करती है :—

1. क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान, जयपुर ।

[सं० ई० 11012/1/77-एच० आई०]

एस० एस० सहस्रनामान, उप सचिव

New Delhi, the 17th June, 1978

**S.O. 1944.**—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the names of the following offices of the Employees' State Insurance Corporation, an autonomous body under the Ministry of Labour, for the purposes of that sub-rule :—

1. Regional Office, Uttar Pradesh, Kanpur.
2. Regional Office, Rajasthan, Jaipur.

[No. E-11012/1/77-HI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 16 जून, 1978

का० प्रा० 1945.—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और रोजगार मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 2653, दिनांक 24 अगस्त, 1966 द्वारा गठित केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक रिक्ति हुई है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री सिसिर कुमार मुकर्जी को 1-6-78 से उक्त औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० एस० 11020/4/78-डी० 1ए(ii)]

New Delhi, the 16th June, 1978

**S.O. 1945.**—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted by the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2653 dated the 24th August, 1966 ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri Sisir Kumar Mukherjee, as the Presiding Officer of the said Industrial Tribunal, with effect from the afternoon of 1st June, 1978.

[No. S-11020/4/78/DIA.(i)]

का० प्रा० 1946.—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और रोजगार मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 2652, दिनांक 24 अगस्त, 1966 द्वारा गठित केन्द्र सरकार श्रम न्यायालय, कलकत्ता के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक रिक्ति हुई है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री सिसिर कुमार मुकर्जी को 1-6-78 से उक्त श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० एस० 11020/4/78-डी० 1ए(ii)]

**S.O. 1946.**—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Central Government Labour Court Calcutta, constituted by the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2652 dated the 24th August, 1966.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri Sisir Kumar Mukherjee as the Presiding Officer of the said Labour Court, with effect from the afternoon of 1st June, 1978.

[No. S-11020/4/78/DIA. (ii)]

का० प्रा० 1947.—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की धारा 13-क के अनु-अनुसरण में, भुवनेश्वर में, भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 1571 तारीख 31 मई, 1963 के अन्तर्गत, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय को ऐसे श्रम न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें कोई भी नियोजक या कर्मचारी ऐसा कोई भी प्रश्न विनिर्दिष्ट कर सकता है जो पूर्वोक्त औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेशों के लागू होने या उनके निर्वचन के बारे में उत्पन्न हो ।

[सं० एस०- 11020/18/77-डी० I(ए)]

एस० के० नारायणयन, डेस्क अधिकारी

**S.O. 1947.**—In pursuance of section 13A of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), the Central Government hereby Specifies the Labour Court, constituted under section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), at Bhubaneswar, constituted under the then Ministry of Labour and Employment Notification No. S.O. 1571 dated the 31st May, 1963 as Labour Court to which any employer or workman may refer any question which may arise on the application or interpretation of a Standing Order, certified under the Industrial Employment (Standing Orders) Act aforesaid.

[No. S-11020/18/77/DIA.]

L. K. NARAYANAN, Desk Officer

भारत

नई दिल्ली, 17 जून, 1978

का० आ० 1948.—मैसर्स स्लेम मैग्नेसाइट प्राइवेट लिमिटेड, स्लेम प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकार जिनका प्रतिनिधित्व मैग्नेसाइट वर्कर्स यूनियन, स्लेम; स्लेम जिला मैग्नेसाइट सेवर यूनियन, स्लेम, मैग्नेसाइट नेशनल सेवर यूनियन, स्लेम के द्वारा किया गया, ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से उनके बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को उपायधन अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के अनुसार औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित करने के लिए सम्मिलित रूप से आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार इससे संतुष्ट है कि जिन लोगों ने आवेदन किया है वे प्रत्येक पार्टी के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री० के० सेल्वारत्नम होंगे और जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

“क्या प्रबंधन मैसर्स स्लेम मैग्नेसाइट प्राइवेट लिमिटेड, स्लेम की दिनांक 24-10-77 को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9क के अन्तर्गत दी सूचना माह्न में सप्ताह में सात दिन कार्य सिवाय राष्ट्रीय व त्योहारों के अवकाशों को छोड़कर और कर्मकारों के भिन्न समूहों को वर्तमान रविवार के साप्ताहिक अवकाश की अपेक्षा सप्ताह के अन्य दिनों में साप्ताहिक अवकाश देने की कारवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुसूची के अधिकारी हैं ?”

[सं० एल०-27025/3/78-डी श्री बी०]

ORDER

New Delhi, the 17th June, 1978

**S.O. 1948.**—Whereas the employer in relation to the management of M/s. Salem Magnesite Private Limited, Salem and their workmen represented by Magnesite Workers' Union, Salem; Salem Distt., Magnesite Labour Union, Salem; Magnesite National Labour Union Salem, have jointly applied to the Central Government under sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), for reference of an Industrial Dispute that exists between them the said application and reproduced in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government is satisfied that the persons applying represent the majority of each party ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal, with Shri K. Selvaratnam as

Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

### SCHEDULE

“Whether the action of the management M/s. Salem Magnesite Private Limited, Salem in giving Notice dated 24-10-1977 under section 9A of the Industrial Disputes Act, 1947 was given to effect the working of the mine all the seven days in a week except on National & festival Holidays and to provide weekly day of rest to different sets of workers on different days of the week instead of the present common weekly day of rest on Sunday is justified ? If not, to what relief the workmen are entitled ?”

[No. L-27025/3/78-D.III.B.]

**S.O. 1949.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Burn Standard Co. Ltd. Salem and their workman which was received by the Central Government on the 13-6-1978.

BEFORE THIRU K. SELVARATNAM, B.A. B.L.,

INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS

(Constituted by the Central Government)

Saturday, the 27th day of May, 1978

Industrial Dispute No. 33 of 1977

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of M/s. Burn Standard Company Limited, Salem).

### BETWEEN

The workmen represented by

The Secretary,

Magnesite Workers Union,

Mamangam, Reddipatti Post, Salem-5.

### AND

The Area General Manager,

M/s. Burn Standard Company Limited,

Salem-636005.

### REFERENCE :

Order No. L-29012/19/77-D.III(B), dated 24th May, 1977 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on for final hearing on Wednesday, the 24th day of May, 1978 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru S. Ramaswami, Advocate for the workman and of Thiru-valargal T. S. Gopalan, P. Ibrahim Kalifulla and S. Ranganathan, advocates for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following

### AWARD

This is an industrial dispute under section 10(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication between the Management of M/s. Burn Standard Company Limited, Salem and their workmen in the matter of dismissal of worker Thiru C. Arumugham.

2. The reference is as follows :

Whether the action of the Management of Messrs. Burn Standard Company Limited, Salem in dismissing Shri C. Arumugham, Peon with effect from 16-9-76 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?

3. A claim statement was filed by the Petitioner-Union, wherein they stated as follows : The Management Charge-sheeted the workman Thiru C. Arumugham for misconduct, viz., (i) that he did not post 31 letters entrusted to him on 15-3-1976 and (ii) that he did not pay back Rs. 96.00 for purchase of postage stamps. As the explanation was not accepted, a domestic enquiry was ordered and there was an enquiry in which he participated. After the enquiry was completed, the Management dismissed him from service by an order dated 16-9-1976. The Enquiry Officer found him not guilty of the first charge. He found him guilty of the second charge which was accepted by the Management. The dismissal was illegal and unjustified. The proceedings suffered from certain infirmities which vitiated the whole enquiry. The findings of the Enquiry Officer were also perverse. The Enquiry Officer had filled up the lacuna in the evidence of M. W. 5 by putting him questions. The Management acted vindictively. Coming to the punishment that he has put in a service of 22 years. The evidence and the dismissal of the worker on the basis of the evidence M. W. 4 who was the principal offender was illegal. In any event the punishment is disproportionate to the gravity of the misconduct by which the worker was charged.

4. A counter statement was filed by the Management, wherein they contend as follows : One Thiru Sugavanam was the Despatching Clerk in the year 1975-76 and he was to keep sufficient stock of stamps for posting the Company's letters and he maintained the Inward and Outward Registers wherein all tapals were registered. On 16-6-1976, Thiru S. Y. Narayanan, an Officer of the Accounts Department noticed the Office Peon Haroon pasting stamps on covers and posting them in the Railway Mail Service, Salem Junction. When Mr. Narayanan questioned Haroon as to why he was purchasing stamps and posting it, the peon replied that as there were no sufficient stamps, the Despatch Clerk gave him cash to purchase stamps for posting the letters. On the next day, Narayanan checked the stamp account. He had a sum of Rs. 850 drawn by him as imprest cash and he found there was a shortage of Rs. 424. Mr. Sugavanam accounted for the shortage by stating that out of the said amount he spent Rs. 113 for his personal expense and he had handed over a sum of Rs. 121 to Arumugham. On an enquiry it was found that Thiru Sugavanam gave Arumugham a sum of Rs. 100 on one occasion for purchase of stamps and another sum of Rs. 25 for purchase of hundi stamp papers. Arumugham purchased revenue stamps for a value of Rs. 4 and he had to account for the balance of Rs. 121. Out of his sum of Rs. 121, Rs. 25 was set apart for purchase of hundi papers and Rs. 96 was retained by Arumugham for the purchase of postal stamps. Thiru Sugavanam asked Arumugham about the sum of Rs. 121. Arumugham told him that he had already spent the money and he would adjust it during the period of Sugavanam's leave by purchasing stamps. On 9th and 10th June, 1976 a sum of Rs. 88.90 was incurred towards purchase of stamps for the covers posted on those two days. On 11th June, 1976 Thiru Sankaranarayanan who was acting as Despatch Clerk drew a cash of Rs. 295.10 towards imprest and he gave Arumugham Rs. 200, out of which Arumugham purchased revenue stamps for Rs. 104. He did not return the balance of Rs. 96 nor did he buy stamps for Rs. 96. When Sankaranarayanan asked Arumugham to account for Rs. 96, he told him that he would purchase stamps on the next day. In those circumstances, he was charge-sheeted. The evidence of Sugavanam and Sankaranarayanan would establish beyond doubt that he had not accounted for Rs. 96 towards purchase of stamps. Even out of the sum of Rs. 200 taken by Arumugham from Sugavanam, he had accounted only for Rs. 192.90 and he has to account for another Rs. 7.10. Further he had not accounted for a sum of Rs. 8 given to him in March, 1976 for posting of 31 letters. From this, it would be clear that he had failed to render accounts for Rs. 103.10. There was a proper enquiry and he fully participated and the evidence clearly established that he misappropriated the Company's money. The Enquiry Officer had come to a proper and correct conclusion and it was not in any way perverse. In these circumstances, the Management has acted rightly in dismissing him. Hence an award may be passed rejecting the claims of the workmen.

5. ISSUE : Out of two charges levelled against him in respect of the first charge, viz., that he failed to post 31 letters entrusted to him with sufficient cash for buying the required stamps he was found not guilty. So it does not arise for consideration. In respect of the second charge,

namely that he had misappropriated an amount of Rs. 96 and Rs. 25 entrusted to him by Despatching Clerk Sugavanam for buying postage stamps and hundi papers it was held that it was proved. In considering the second charge, this Tribunal has to decide only two points, namely, (i) whether the Management succeeded in establishing that the worker Arumugham was guilty of misappropriation of Rs. 96 entrusted to him by the Despatching Clerk Thiru N. V. Sugavanam for purchase of postage stamps ; and (ii) whether the punishment awarded to him is disproportionate to the gravity of the charge.

6. POINT No. 1 : So far this point is concerned the earliest statement by way of explanation Ex. M-6 is quite relevant. His explanation was that Rs. 96 was not given to him for purchase of stamps. His statement would imply that he had received the amount from Sugavanam but it was not for purchase of stamps. If he was innocent he could have given a convincing statement that in what circumstances the amount was given to him and what for the amount was intended. At the earliest point of time it is his duty to explain under what circumstances he came in possession of Rs. 96 and his failure to give explanation is a circumstance against him. Under the proceedings Ex. M-11, I find Arumugham made a statement before the Enquiry Officer. His statement was, that before Sugavanam went on leave, he asked him for a loan of Rs. 100 and he promised to him to give that amount but he could not find money and he agreed to make up Rs. 50. Sugavanam asked him to adjust for two days till his return and after his return from leave he will adjust things. Since he was not able to raise money he could not give the loan amount as promised. Sankaranarayanan gave him Rs. 200 for purchase of stamps, out of which he purchased stamps for Rs. 104 and balance of Rs. 96 was in his hand. Out of the said amount he had purchased stamps for Rs. 87.70 and the balance of Rs. 8 was with him and as the Hundi papers were not available he was retaining the amount of Rs. 25. As against the statement, the evidence of Sugavanam M.W.4 and Sankaranarayanan M.W.5 are relevant. The evidence of Sugavanam was when the accounts were checked there was shortage of Rs. 424 and explained the same that he had lost Rs. 190 and the balance of Rs. 113 was taken by him for personal expenses and he had paid Rs. 121 to Arumugham. It is evidenced that out of Rs. 121, Rs. 25 was admittedly retained by Arumugham for the purchase of Hundi papers and the balance of Rs. 96 was still with Arumugham. He has stated that he had paid the amount to Arumugham on 7-6-1976. When he questioned him whether he purchased the same, his statement was that he had no time for purchase of stamps and he promised to purchase the stamps on the next day. Before handing over charge to Sankaranarayanan he asked Arumugham regarding stamps and Arumugham stated that he had spent the amount and he would pay the amount to Sankaranarayanan. He had purchased revenue stamps for Rs. 4. M. W. 5 Sankaranarayanan stated that he questioned Sugavanam before taking charge for the shortage of amount, Sugavanam stated that Arumugham would pay Rs. 96 and asked him to adjust for two days. Therefore the evidence of both would make it abundantly clear that Rs. 96 belonging to the Company was with Arumugham. Admittedly he had not purchased stamps for despatch of tapals. Therefore, the only inference is that Arumugham had misappropriated the amount. It is no doubt true that the evidence of Sugavanam in the nature of an accomplice but in matters like domestic enquiry, there is no bar on relying on such evidence. Even Arumugham had not denied the receipt of Rs. 96 from Sugavanam but what he state is that he received that amount from him not for purchase of stamps. Having regard to the evidence in this case, the only conclusion that one can arrive is that he had misappropriated the money belonging to the Company and converted the money entrusted to him for purchase of stamps into his own personal use. Therefore the charge has been proved. The finding of the Enquiry Officer cannot be said to be in any way perverse. The delinquent had full opportunity to defend himself and the Enquiry Officer has given a finding only on the evidence adduced on both sides. Hence my finding is in the affirmative.

7. POINT NO. 2 : As regards punishment, it is contended that the punishment is excessive. The learned counsel appearing for the Management would contend that the misconduct for which he was charged was a serious one and as such the proper punishment can be only dismissal. He has also pointed out that the Management was willing even to condone misconduct like disobedience, or an assault, but

the Management is not willing to condone the embezzlement by an employee which would be a bad precedent. If the Tribunal inflicts a lesser punishment and order reinstatement it will demoralise the discipline. Since two years had passed, the Tribunal may not order reinstatement. He would point out that the misconduct of embezzlement of the Company's money is considered as a serious misconduct both under the Payment of Gratuity Act, 1972 and the Payment of Bonus Act, 1965. Under the Payment of Gratuity Act, 1972, Section 4 (6) (b) sub-clause (ii), a person is denied the benefit or gratuity if the employee's services have been terminated which involves moral turpitude. Under Section 9 (c) of the Payment of Bonus Act, 1965, bonus is denied for misappropriation. The learned counsel would urge that the Tribunal is precluded from giving lesser punishment. No doubt the offence of embezzlement is a serious one, but the Tribunal can take into account the peculiar circumstances and facts of each case while inflicting punishment. Here he is an ill-paid employee (peon) and he is not entrusted with money by the Company. But the person entrusted with money is Despatching Clerk and his duty is to purchase stamps and hand over them to the peon who has to affix them. Undoubtedly in the present case we find Sugavanam is the main culprit who has misappropriated a part of the amount entrusted to him for the purchase of stamps and to cover up his activities he has allowed his peon Arumugham to handle the money of the Company in an unauthorised manner. Naturally, Arumugham was tempted to misappropriate the money and he became victim of circumstances. Therefore having regard to the facts and circumstances and having regard to the sum involved, I find the Tribunal cannot apply the rule rigidly. However, the Management has taken a very stiff attitude towards the employee Arumugham for reinstatement. Therefore, this Tribunal does not want to force this employee on the unwilling Management. I find he has put in 22 years of service and the amount involved is only Rs 96. Therefore my finding is, the order of dismissal is excessive which will entail the forfeiture of bonus and gratuity for the years he served. There is also no record to show that his antecedents were bad. In these circumstances, the proper order would be the order of discharge and not dismissal, so that he can draw his gratuity amount as well as bonus. In addition to that on compassionate grounds I am directing the Management to pay him three months salary.

6. In the result, an Award is passed negating the demand of the workman for reinstatement and the order of dismissal is modified as one of discharge, so that he can claim the bonus and gratuity to which he is entitled to for the years he served and in addition he would be entitled to three months salary on compassionate grounds.

Dated, this 27th day of May, 1978.

K. SELVARANAM, Presiding Officer.

#### WITNESSES EXAMINED

for both sides : Nil.

#### DOCUMENTS MARKED

For worker : Nil.

For Management :

- Ex. M-1/17-6-76—Letter from Thiru S. Y. Narayanan to the Works Accountant regarding Stamp account.
- Ex. M2/19-6-76—Letter from Thiru Sugavanam to the Works Accountant regarding Postage account.
- Ex. M-3/21-6-76—Letter from the worker to the Works Accountant.
- Ex. M-4/26-6-76—Show cause notice issued to Thiru C. Arumugham.
- Ex. M-5/26-6-76—Show cause notice issued to Thiru N. V. Sugavanam.
- Ex. M-6/28-6-76—Explanation of Thiru C. Arumugham to Ex. M-4.
- Ex. M-7/29-6-78—Explanation of Thiru V. Sugavanam to Ex. M-5.

Ex. M-8/12-7-76—Charge sheet issued to Thiru C. Arumugham.

Ex. M-9/14-7-76—Letter authorising the Works Accountant-cum-Office Manager to represent the Management in the enquiry.

Ex. M-10/15-7-76—Letter from Thiru C. Arumugham for permitting Thiruvalluvar Balasubramanian and Venkatachalam in the enquiry.

Ex. M-11—Enquiry Proceedings. (copy).

Ex. M-12/7-8-76—Findings of the enquiry officer.

Ex. M-13/16-9-76—Dismissal order issued to Thiru C. Arumugham.

Ex. M-14—Despatch register for the period from 24-5-1976 to 26-6-1976.

Ex. M/15—Despatch register for the period from 21-2-1976 to 22-5-1976.

K. SELVARATNAM, Presiding Officer

[No. L-29012/19/77-D. III B.]

JAGDISH PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 जून, 1978

का० भा० 1950—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में कल्याण श्रावुक, लोह खनिक खान श्रम कल्याण संस्था, इन्दौर, मध्य प्रदेश कार्यालय को, जिसके कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यमाध्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है।

[सं० ई० 11017/2/78-एम० चार]

पि० के० सेन, अवर सचिव

New Delhi, the 19th June, 1978

S.O. 1950.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Office of Welfare Commissioner, Iron Ore Mines Labour Welfare Organisation, Indore, Madhya Pradesh the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

[F. No. E-11017/2/78-MIV]

P. K. SEN, Under Secy.

S.O. 1951.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Kanji Jadhavji and Company, Bombay and their workmen which was received by the Central Government on the 20th June, 1978.

#### Reference No. CGIT-2 of 1977

PARTIES :—Employers in relation to M/s. Kanjit Jadhavji & Co., Bombay,

AND

Their workmen.

#### APPEARANCES :

For the employees : Shri A R. Sulni, Advocate

For the workmen : Shri K. R. Dengle, Advocate.

INDUSTRY : Port & Dock.

STATE : Maharashtra.

Dated, Bombay, the 12th June, 1978

#### AWARD

1. The Central Government, in exercise of powers conferred under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act,

1947, has referred the following dispute for adjudication by this Tribunal :—

#### "THE SCHEDULE"

Whether the action of the Management of Messrs Kanji Jadhavji and Company, Bombay in terminating the services of Shri V. B. Nalvade, Foreman, by way of retirement as per their Notice No. JB/PD/ST/929/76, dated 6th August, 1976 is justified? If not, to what relief is Shri Nalvade entitled?"

2. The Transport & Dock Workers' Union, who has espoused the case of the workman, has filed its statement of claim wherein it is stated that the workman, Shri V. B. Nalvade, joined the Company in 1944 and was working as a Head Foreman and that the contracts governing employment of members of the staff have neither fixed the age of retirement nor has the firm given a notice of change fixing the age of superannuation. It is further stated therein that the workman had a right to continue in employment until incapacitated to perform his duties as per the contract of employment and in the absence of a term regarding superannuation or retirement. There are several members of the staff in the Company who are more than 60 years of age and they have not been retired. The workman was asked to submit to medical examination of one Dr. D. D. Bamji who found him hale and hearty. The Company by letter dated 9-1-1976 to the Union suggested that the employee was old and not fit for duties as a Foreman and he had been allowed because the employer had good tonnage. But now it was not possible for the company to continue the workman in question. The Union by its letter dated 24-1-1976 repudiated the version of the employer that the employee was old and not fit for duties as Foreman, and asked the employer not to pursue the vindictive attitude. By letter dated 6-8-1976 the Employer terminated the services of the employee. The order of termination by way of retirement or superannuation is challenged on the ground that there is no age of retirement or superannuation stipulated in the contract of employment and that there are also no standing orders and that the order is mala fide and amounts to unfair labour practice and victimization.

3. The Company has filed its written statement challenging the jurisdiction of this Tribunal inasmuch as the employee was working as a Head Foreman and his duties consisted mainly the supervisory work. On the date of retirement from service his salary was Rs. 1,276.50 and, as such, he was not a workman within the meaning of Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947. Since the business of the Company deteriorated it was not possible for the Company to keep a large number of employees on its roll. If it did not terminate the services of several employees it was as a gesture of goodwill.

Although there were adverse reports against the employee the Company did not take any penal action against him and his services were terminated in the normal course upon his completing 60 years of age. Regarding the age of retirement/superannuation the Company has followed the practice/convention prevailing in respect of the Stevedoring staff. The Company denied that it took any vindictive action which is mala fide or amounted to unfair labour practice.

4. Section 2(s) of the Industrial Disputes Act defines a workman. It also says that the workman does not include such a person who being employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding Rs. 500 per mensem. In order to establish that he is a workman within the meaning of Section 2(s), the workman (WW-1) has stated that when he was retired he was working as Mazdoor in the Company. According to him, his duties were to prepare a sling, to stitch the sling, to pull the hand-carts and to work wherever he was directed to work and that he had no authority to appoint or dismiss the workers. There are strong reasons why the contention of the workman that he was not a Foreman at the time of retirement, cannot be upheld. Firstly, in the statement of claim the Union on more than one occasion, has described him Foreman and has also referred to him as a Head Foreman. The Secretary of the Bombay Stevedores Association has been examined as EW-1. The employer Company is a member of this Association. The agreements and settlements between the different Companies and the Stevedores Association are said to be applicable to the employer Company also. Ext. E-4 is the list of duties of a Foreman and a perusal of this list shows that his duties are mainly supervisory. I think that on the basis of such a material and as the salary of the employee at the age of retirement/superannuation exceeded Rs. 500 per

mensem, he cannot be held to be a workman and that being so, this Court has no jurisdiction to make any award.

5. Now as to the merits. The case of the employer Company is that the employee was retired when he attained the age of 60 years. In order to show that at the time of retirement he had not attained the age of 60 years reliance is placed upon the Birth Register (Ext. W-4) and the two affidavits (Exts. W-2 & 3). Ext. W-1 is the letter of termination dated 6-8-1976. It informed the employee that his services will come to an end on account of attaining the age for retirement and superannuation and, therefore, his services will stand terminated with effect from the next month. The Birth Register (Ext. W-4) shows that a child by name Krishna was born on the 4th October, 1918. The name of the employee is Vishnu. The evidence of the workman is that his cradle name was Krishna and when his name was enrolled in School it was registered as Vishnu. To that effect two affidavits (Exts. W-2 & 3) have been filed. Ext. W-2 dated 2-8-1977 is an affidavit sworn by the workman himself before the Taluka Magistrate saying that his date of birth is 4-10-1918 and that his cradle name was Krishna and it was registered as Vishnu in the school and in his service record. Ext. W-3 dated 11-8-1977 is another affidavit filed by his brother before the Taluka Magistrate reiterating the same fact. It is difficult for me to place reliance on these affidavits. The reason is that the clear evidence of the employee (WW-1) is that he had not gone to any school. That being so, his statement that when he "started attending school" he was named as Vishnu cannot be upheld.

6. The evidence of the employee is that even before 11-9-1976 he had produced the certificate about his age and the affidavits before the Company, but in spite of that his services were terminated. Clearly this cannot be believed since the two affidavits were sworn to in August, 1977. The copy of the Birth Register says that the application for the same was made on 2-8-1977 and it was delivered to him on that date, and that being so it could not have been shown to the Company on the date as claimed by the workman. Even if one Krishna was born on the 4th October, 1918 there is no acceptable evidence to connect it with the employee whose name is Vishnu. That the age of retirement/superannuation is fixed at 60 years appears from the letter dated 30-6-1977 (Ext. 5). The materials on which the employee sought to reply that he had not attained the age of superannuation, having been rejected, there is nothing to doubt the case of the employer that it was on attaining the age of 60 years that the workman had been retired from service.

7. For the reasons given above, my award is that this Tribunal has no jurisdiction to entertain this Reference and that action of the Management of Messrs Kanji Jadhavji & Company, Bombay in terminating the services of Shri V. B. Nalvade, Foreman, by way of retirement as per their Notice No. JB/PD/ST/929/76, dated 6th August, 1976 was justified and that Shri V. B. Nalvade is entitled to no relief.

J. NARAIN, Presiding Officer

[No. L-31012(1)/77-D.IV(A)]

**S.O. 1952.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of New India Assurance Company Limited, Bombay and their workmen which was received by the Central Government on the 19th June, 1978.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

Reference No. CGIT-1 of 1977

Employer in relation to M/s. New India Assurance Co. Ltd., Bombay.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the employer—Shri C. V. Pavaskar, Labour Adviser.

For the workmen—

(1) Shri C. L. Dudhia, Advocate. } Union Executives  
(2) Shri N. B. Karmaran, }

- (3) Shri D. G. Khadekar. }  
 (4) Shri K. S. Murty. } Union Executives.  
 (5) Shri G. D. Gum. }

INDUSTRY : Assurance STATE : Maharashtra.

Dated, Bombay, the 26th May, 1978

### AWARD

1. The Central Government in exercise of powers conferred under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dispute for adjudication by this Tribunal :—

### "THE SCHEDULE

Whether the action of the management of New India Assurance Company Limited, Bombay in not categorising the Assistants to Marine Surveyors into the Staff Assistants Grade from the date they were working as Marine Surveyors/Loss Assessors and also denying them the Superintendents Grade after the introduction of General Insurance (Nationalisation and Revision of Pay scales and other conditions of service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 is justified? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?"

2. Regard being had to the objection raised as to the jurisdiction of this Tribunal to entertain this Reference, it would not be necessary to refer to the facts of the case in detail. Suffice it to say that in 1961 the New India Assurance Company Limited had recruited certain persons and designated them as Marine Surveyors and fixed them in the then Staff Assistants' grade and some other persons were recruited as Assistants to Marine Surveyors in the then 'B' grade. The said grades prior to 1-1-1973 were as under :—

#### (1) Staff Assistants' Grade :

Rs. 355—20—415—EB—25—515—30—665.

#### (2) 'B' Grade :

Rs. 170—8—210—10—310—EB—15—385—20—465.

The case of the New India Assurance Co. Ltd. Employees' Union on behalf of their workmen is that initially the Assistants to Marine Surveyors were required to assist the Marine Surveyors in their administrative work but later they began doing the survey work independently. In about 1970, in view of the Insurance Amendment Act 1969, the Marine Surveyors/Loss Assessors were required to register and obtain licence from the Controller of Insurance. The Management applied for licence in May, 1970 in respect of 12 employees including one Marine Surveyor and the concerned Assistants to Marine Surveyors. As per the requirements for obtaining such licences, a declaration had to be made by the applicant stating the fact that he had surveyed and signed the Survey Report in respect of claims preferred on any General Insurance Company which had either employed him or assigned him the work of conducting marine survey work. The New India Assurance Company Ltd. applied for the said licence on behalf of all those who were doing the work of Marine Surveyor/Loss Assessor including those workmen concerned in the instant dispute and also enclosed copies of the survey reports prepared by them, to the Controller of Insurance, Government of India. Accordingly, the Controller of Insurance issued the licences of Marine Surveyor/Loss Assessor to these persons for the period of five years and the same were renewed on the expiry of the said period. The Union took up negotiations with the Company as regards the status of the Assistants to Marine Surveyors who were actually working as full-fledged surveyors and asked the Management that they should be given the grade of Staff Assistants but it was not done so. The Management categorised only five out of 9 Assistants to Marine Surveyors in the grade of Staff Assistants. The Federation was not satisfied with this. The remaining workmen including others made a representation to the Chairman-cum-Managing Director of the Company in October, 1974 to this effect. There were discussions and ultimately a formal demand was made by the Federation and the

matter has, thus, been referred for adjudication by his Tribunal.

3. By its written statement the Management has taken up the position that this Tribunal has no jurisdiction to decide the present claim of the Applications. According to them the question of categorisation of employees is exclusively governed by the provisions of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974. This Scheme came into force with effect from 27th May, 1974. In view of the paragraph 5 of this Scheme, the ultimate decision regarding categorisation of employees falls within the exclusive domain of the Custodian only. The Scheme has been amended and it provides for an Appeal against the decision of the Custodian to the Board of the Company and, as such, this Tribunal has no jurisdiction to entertain this Reference.

4. In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of Section 16 of the General Insurance Business (Nationalisation), Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government framed a Scheme known as General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974. This Scheme provides for the rationalisation and revision of pay scales and other terms and conditions of service of employees of the Company. Paragraph 5 of the Scheme speaks of categorisation of employees. It is stated in sub-paragraph (5) of that paragraph that the decision of the Custodian regarding the category to which an employee shall be assigned for the purpose of fitting such employee in the new scale shall be binding on the employee. The Scheme was amended from time to time. By the Second Amendment Scheme, 1976, a provision has been made for appeal. For the above paragraph, the following sub-paragraphs have been substituted :—

"(5)(a) Any employee aggrieved by the decision of the Custodian under this paragraph may prefer an appeal to the Board of the Company to which such employee belongs within thirty days of the receipt by him of the decision of the Custodian :

Provided that where any employee is aggrieved by the decision of the Custodian made before the commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Second Amendment Scheme, 1976, such employee may within sixty days of such commencement prefer an appeal to the Board of the Company to which such employee belongs.

(b) The Board of the Company or the Committee thereof shall decide the appeal :"

5. Thus this Scheme, so to say, is a complete code in itself. It provides for a forum where an employee can agitate his grievance and it also contains a provision for appeal against the decision of that forum. Sub-section 7 of Section 16 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 lays down that "the provisions of this section and of any scheme framed under it shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or any agreement, award or other instrument for the time being in force." In view of such a clear provision and the Scheme being what has been referred to above, there is no escape from the position that this Tribunal has no jurisdiction to entertain this Reference.

6. For the above reasons, it must be held that this Tribunal has no jurisdiction to entertain this Reference and, accordingly, the Reference is incompetent.

7. The Reference is answered accordingly.

J. NARAIN, Presiding Officer

[No. L-17011(10)/76-D. IV(A)]

NAND LAL, Desk Officer



New Delhi, the 21st June, 1978

**S.O. 1953.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Lakshmi Commercial Bank Ltd., New Delhi, and their workmen over non absorption of Shri Shiv Nath Sharma as a clerk and terminating his services w.e.f. 21-8-74 which was received by the Central Government on the 6-6-78.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

**I. D. No. 92 of 1977**

BETWEEN

Shri Shiv Nath Sharma, Mohalla Kotla Pajaba, Firozabad (Agra) ...Petitioner

Versus

The General Manager, Lakshmi Commercial Bank Ltd., Connaught Circus, New Delhi. ...Respondent

AWARD

The Central Govt. vide its order No. L-12012/151/75/DII/A dated the 22nd October, 1975 made a reference u/s 10 of the I. D. Act, 1947 in the following terms to Industrial Tribunal, Kanpur.

"Whether the action of the management of Lakshmi Commercial Bank Limited, New Delhi in not absorbing Shri Shiv Nath Sharma as a clerk and in terminating his services with effect from the 21st August, 1974 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"

2. After usual notices were sent to the parties, the parties filed their respective statements of claim and the reply to those respective statement of claim were got filed and before issues could be framed the reference was transferred to Central Tribunal, Delhi and the Central Tribunal, Delhi relinquished the charge of the post of Presiding Officer and in consequence the case was transferred to this Tribunal for disposal and usual notices were issued to the parties to appear before this Tribunal and finally the parties appeared before this Tribunal and on the 10th April, 1978 Shri Daya Nand Munjal, Chief Personal Manager and general attorney of the Lakshmi Commercial Bank Ltd. made the following statement on this file :

"The parties have settled the matter under dispute vide settlement Ex. S/1. It bears my signatures as also the signatures of Shri Brijendra Singh, State Vice President of UP Bank Employees' Union and the matter stands settled in accordance with Ex. S/1. This settlement has been acted upon and accordingly the award may be made in terms of the settlement."

The statement of Shri Daya Nand Munjal is corroborated by Shri N. C. Sikri, Advocate for the Bank. None had appeared for the workman or the Union on the date fixed in this case i.e. 27th April, 1978. I have perused the settlement. From the perusal thereof I find that certainly the matter have been settled and accordingly a no dispute award is passed in this matter leaving the parties to bear their own costs.

MASHESH CHANDRA, Presiding Officer  
[F. No. L-12012/151/75-D.II.A]

Dated : the 27th April, 1978

**S.O. 1954.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Life Insurance Corporation of India and their workmen over non-inclusion of the name of Smt. S. Rajan, Assistant P & G Department in the Ranking List of Higher Grade Assts. of Western Zone which was received by the Central Government on the 6-6-78.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

**Reference No. CGIT-33 of 1975**

Employers in relation to the Life Insurance Corporation of India

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—1. Shri A. W. Dharwadkar, Deputy Secretary (Personnel) 2. Shri Y. Ramchandran, Administrative Officer (Personnel).

For the workmen—Shri S. R. Chaubal, General Secretary, Insurance Employees Association, Bombay.

INDUSTRY : Insurance STATE : Maharashtra.

Bombay, dated the 6th April, 1978

AWARD

The Government of India, in the Ministry of Labour, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Life Insurance Corporation of India in not including the name of Smt. S. Rajan, Assistant, P & G Department in the Bombay Divisional Office in the Ranking List of Higher Grade Assistants for Western Zone and consequently depriving her of her promotion to that grade is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"

After the notice was issued to the parties to file their respective written statements, etc., the Union filed its written statement of claims and the management also filed its written statement. The matter was fixed for hearing on various occasions and was adjourned for one or the other reason. However, at the hearing on 11-4-1978, the parties filed a Joint Application stating that they had arrived at an agreement whereby the management owned promote to the cadre of Higher Grade Assistant and the workman Smt. S. Rajan, shall accept the said promotion with effect from 6th April, 1978. The Parties have also agreed that the agreement as above shall be in full and final satisfaction of all the claims of the workman in the dispute in the present reference and they pray this Hon'ble Tribunal be pleased to make an Award in terms thereof.

I find the terms of the agreement fair and reasonable and make my Award in terms thereof. No order as to costs.

J. NARAIN, Presiding Officer

[F. No. L-17012/4/75-D.II.A.]

**S.O. 1955.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen over not allowing Shri Ram Lal Molhotra (Mook) to officiate in higher cadre which was received by the Central Government on the 6-6-78.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

**I. D. No. 189 of 1977**

BETWEEN

The State Vice President, Punjab National Bank Employees' Union, 295/387, Deen Dayal Road, Ashrafabad, Lucknow (Ram Lal Malhotra) ...Petitioner.



## Versus

The Regional Manager, Punjab National Bank, Hasratganj,  
Lucknow. ...Respondent.

## PRESENT :

Shri O. P. Nigam—for the Workman.

Shri G. B. Singh—for the Management.

## AWARD

The Central Government as appropriate Government made the following reference u/s 10 of the I. D. Act, 1947 vide its order No. L-12012/27/77-D. II. A dated the 20th August, 1977 :

"Whether the action of the management of the Punjab National Bank for not allowing Shri Ram Lal Malhotra (Mook) to officiate in the higher cadre for the period from 11-10-75 to 11-10-76 is justified or not? If not, to what relief he is entitled?"

2. After receipt of the reference usual notices were issued to the parties and the parties filed their respective written statements as also documents. Then the rejoinder to the respective written statement were got filed by the respective parties and before any further proceedings could be recorded the parties arrived at a compromise and the compromise was recorded vide my order dated the 28th April, 1978 inasmuch as it was found in the interest and for the benefit of the workman. The said compromise and settlement is Ex. S/1. The statements of Shri O. P. Nigam and Shri G. B. Singh were recorded for the Workman and the Management and they have stated 'Parties have arrived at a settlement. Settlement is Ex. S/1. It bears our signatures. A no dispute award may be given. Parties be left to bear cost. In terms of the settlement accordingly a no dispute award is hereby made leaving the parties to bear their own costs.'

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

[F. No. L-12012/27/77-D.II.A]

**S.O. 1956.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of India and their workmen over withdrawal of special allowance of Cashier in charge from Shri S. K. Mishra Cashier-in-Charge Purwa Branch of the Bank which was received by the Central Government on the 6-6-73.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

## I. D. No. 33 of 1977

## BETWEEN

The President, Bank of India Staff Union (UP Branch),  
C/o Bank of India, Mohini Mansion, 2nd Floor,  
Naval Kishore Road, Lucknow ...Petitioner

## Versus

The Regional Manager, Bank of India, Mohini Man-  
sion, No. 1, Naval Kishore Road, Lucknow

...Respondent

## PRESENT :

Shri S. K. Mishra, workman himself.

Shri Y. K. Arora,—for the Union.

Shri P. K. Banerjee, for the Management.

## AWARD

The Central Govt. as appropriate Govt. vide its order No. L-12012/105/77-D. II. A dated the 7th March, 1978 made the following reference u/s 10 of the I. D. Act, 1947; to this Tribunal :

293 GI/78—5

"Whether the action of the management of Bank of India in withdrawing the special allowance of Cashier-in-charge from Shri S. K. Mishra, Cashier-in-charge Purwa Branch of the Bank w.e.f. 1-11-76 without giving him any notice or an opportunity to explain his conduct is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. After the reference was registered usual notices were issued to the parties to appear and in pursuance thereof parties appeared but before the parties filed a statement any written statement, a settlement was arrived at between the parties. After perusal of the settlement Ex. S/1, I find that it was for the benefit of the workman and therefore it was ordered to be recorded. Accordingly the statement of Shri S. K. Mishra, Y. K. Arora and P. K. Banerjee were recorded for the Workman and the Management respectively in which it was stated by them 'that the parties have settled the dispute vide Ex. S/1. A no dispute award be made.' According a no dispute award is hereby made in this reference, leaving the parties to bear their own costs.

[F. No. L-12012/105/77-D. II. A.]

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Dated : 28th April, 1978.

**S.O. 1957.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Algemene Nederland N.V., and their workmen over the termination of the services of Shri J. G. Jha, Cashier which was received by the Central Government on the 6-6-78.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

## Reference No. CGIT-9 of 1976

## PARTIES :

Employers in relation to Algemene Bank Nederland  
N.V., Bombay.

V/s.

Their workmen.

## APPEARANCES :

For the workmen.—Shri B. W. Valdia Advocate.

For the employer.—(1) Shri S. D. Vimadlal, Advocate.

(2) Shri V. V. Pai, Advocate.

## INDUSTRY :

Banking

## STATE :

Maharashtra

Bombay, the 18th May, 1978

## AWARD

1. The Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), has referred the following dispute for adjudication by this Tribunal :—

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of Algemene Bank Nederland N. V., Bombay in terminating the services of Shri J. G. Jha, Cashier, Zaveri Bazar Branch of the Bank is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The General Bank of the Netherlands Employees' Union, on behalf of the workman, filed the statement of claim. According to them, employees of the Bank are governed by Shastri Award modified by Desai Award and further modified by settlement between the Bank and the Employees' Unions in the matter of service conditions, pay scale etc. They have laid down the procedure for disciplinary proceedings. The workman, Shri J. G. Jha, was employed as a

Cashier attached to the Zaveri Bazar branch of the Bank. By its letter dated 2-6-1976 the Bank terminated the services of Shri J. G. Jha on the ground that the Bank had lost confidence in him. The Bank offered to pay three months' pay and allowances in lieu of three months' notice and credited the same in his account. By his letter dated the 7th June, 1976 Shri J. G. Jha pointed out that the order of termination was in gross violation of the conditions of service as well as violative of rules of natural justice and requested the Bank to reconsider the decision. The Bank declined to do so. Thereafter the General Bank of the Netherlands Employees' Union by its letter dated 19-6-1976 requested the Bank to reinstate the employee on the grounds mentioned by them and addressed a letter to the Regional Labour Commissioner (Central) to use his good offices to get Shri Jha reinstated. It was pointed out in the conciliation proceeding that the Management had not followed the procedure for disciplinary proceedings. The Assistant Labour Commissioner, however, submitted his failure report. The contention of the Union is that the order of termination dated 2-6-1976 is illegal on the following grounds :—

- (a) The order is penal and it was issued without following the procedure for imposing a penalty.
- (b) The order is mala-fide.
- (c) The order is violative of principles of natural justice and it amounts to victimisation and to unfair labour practice.
- (d) It was incumbent upon the Bank to follow the procedure in relation to disciplinary proceedings.
- (e) The order is bad and illegal as in the guise of "loss of confidence" the Bank has in fact dismissed Shri J. G. Jha.

The Bank ordered termination of services of Shri J. G. Jha and he was not paid retrenchment compensation at the time of termination of his services. The prayer is that it may be declared that the order of the Bank in terminating the services of Shri J. G. Jha was unjustified and the Bank be ordered to reinstate him with retrospective effect from 2-6-1976.

3. The Bank has filed its statement of claim saying that it was a case of bona fide act of termination and not a case of disciplinary action or punishment and carries to stigma. The Bank was extremely indulgent and kind to Shri J. G. Jha, but on account of repeated shortages of cash he forfeited the trust and confidence of the Bank. Shri Jha could not be trusted with the handling of large sums of money and the credit and reputation of the Bank was to be increasingly in jeopardy. The Bank has denied that the order of termination is mala fide. The order of termination of services of Shri J. G. Jha was passed under provisions of the paragraph 522(1) of the Sastry Award which expressly provides for a case where no disciplinary action for misconduct is involved. Shri Jha was a Cashier and sometimes acted as a Chief Cashier and his duties, mainly, were to receive cash and/or to pay cash to customers, handling and clearing of cheques the balancing of totals etc. which were highly responsible and trustworthy works and in which he was found most unreliable and untrustworthy. He came into the employment of the Bank as Cashier in 1968. From 1970 onwards, there had been various incidents of late coming and careless attention to work and lapses, upsetting the smooth working of the Bank. He frequently remained absent without prior intimation or permission. Thus, for example, on 25-8-1971 and 17-3-1972 he remained absent without prior permission and without any valid reason; on 23-8-1974 he left the office two hours before the scheduled time without permission and on 25-8-1975 he remained absent without prior permission and intimation. This kind of conduct had caused a lot of inconvenience and disruption, and exposed the Bank to unnecessary risk. Whenever he was made aware of his lapses and shortcomings, he gave assurances that they would not be repeated, but he failed to keep up his promise. He also left the Cash Counter during business hours for which he was warned. Sometimes he refused to find out clearing differences in the day's tally only to work overtime for the purpose and when he wanted to earn overtime, he deliberately seemed to keep his work incomplete and unbalanced. On several occasions, he made wrong entries and committed errors in filling in slips or

totalling for collection or omitted to write on clearing slips the commission amounts as required. Several of these incidents were between 1971 and 1973. The Bank was given specific incidents of particular dates. (a) On or about 24-11-1970 in the main outward clearing, an amount of Rs. 23,888.57 was left out by Shri Jha from the settlement with the State Bank of India. On being questioned, he said it was a machine error, but it was not found correct. The relative claim memo to the State Bank of India was not delivered till 27-11-1970, thus inflicting loss by way of interest to the Bank; (b) On or about 26-11-1970 while going to the clearing house with the main outward clearing cheques, Shri Jha forgot or omitted to take three bundles of cheques and a Sepoy had to be rushed to the Clearing House of the Bank at 12.50 P.M. to fetch the missing bundles; (c) In or about November, 1970 there was a difference in the tally in the evening in Shri Jha's handling and it was only when other officers joined in assisting in the search that the missing cheque was recovered from the floor where Shri Jha worked; (d) On or about 16-2-1973 he issued a cheque for Rs. 2,000 on his Savings Bank account when the balance to his credit was only Rs. 6.18. He could not pay in any sum and the cheque had to be returned; (e) On or about 22-2-1973 certain cheques received to be presented in clearing were lying on Shri Jha's table till 2-15 P.M. without being filled in for depositing in the clearing before 2-30 P.M. The Bank authorities had to specifically hurry the deposit of the cheques in time as otherwise the balance could not be tallied for the day. For this he was cautioned; (f) On or about 2-2-1974 he was working as a paying cashier while the receiving cashier was one Mr. Gaitonde who was a probationer. There was found a shortage of Rs. 9,910 in Shri Gaitonde's cash and Shri Jha also reported the same. On checking Shri Jha's cash, it was found that he had an excess of Rs. 10,000/-. It appeared that this represented cash transferred by Shri Gaitonde to Shri Jha in the course of the day's handling. The practice would be to obtain Shri Jha's acknowledgement for this, but Shri Gaitonde was a new probationer and Shri Jha never instructed him to follow the correct practice. At first Shri Jha denied having received the sum of Rs. 10,000/- from Shri Gaitonde, but later did not persist in his denial. Ultimately the cash was balanced taking the sum of Rs. 10,000/- as excess from Shri Jha's cash; (g) On or about 4-6-1973 there was a shortage of Rs. 100/- which was reimbursed by him on the same day; (h) On or about 10-4-1973 there was a shortage of Rs. 200/- in Shri Jha's bundle which was found out on the next day, but responsibility could not be fixed; (i) On 28-1-1974 there was a shortage of Rs. 25/- which was paid by him the same evening; (j) On 16-2-1974 there was a shortage of Rs. 100/- and on 3-9-1974 there was a shortage of Rs. 1,800/- which was allowed to be paid by him by instalments against a loan granted for the purpose; (k) On or about 28-5-1976 two serious incidents took place. There was a shortage of Rs. 1,000 reported in Shri Jha's handling. Shri V. P. Nair, Staff Officer of the Bank went to the Zaveri Bazar Branch and made enquiries. On being questioned Shri Jha suggested that the mistake might have been in the bundles sent by the Reserve Bank of India. When, however, the facts were brought to his notice that it could be so, Shri Jha changed his attitude and offered to make good the loss or shortage and gave it in writing. The second incident was in respect of various old, soiled, torn and repaired notes in the bundles of notes handled by the Cashier, Shri Jha, in the evening of 28-5-1976. There were a number of old, soiled, torn and repaired notes. Some of the bundles were so initialled as to mislead the authorities into thinking that they were the initials of the other receiving cashier, Shri Rao. There being complete loss of confidence in Shri Jha the Bank terminated his services by its order dated 2-6-1976 on payment of three months' pay and allowances in lieu of three months' notice. By an amendment which was allowed, it was alternatively contended that the order of termination of services of Shri Jha was in reality a dismissal order for acts of misconduct and for this the Bank may be permitted to treat its action as one of dismissal without an enquiry being held and sought permission to prove the acts of gross misconduct by adducing necessary evidence.

4. A rejoinder was filed on behalf of the workman by the Bank of Netherlands Employees' Union wherein it was contended that the termination of service has penal consequences and it cast a stigma on the workman and, as such, it was incumbent upon the Bank to follow the procedure laid down in clause 19 of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966.

It has been further contended that it was imperative on the part of the Bank to hold an enquiry and to give a reasonable opportunity to Shri Jha to show cause. With reference to the shortage of Rs. 1,000 on 28th May, 1976, the case of the Union is that it was incumbent upon the Bank to follow the proper procedure and to hold an enquiry and that the action taken in this regard is penal and by way of victimization. With reference to the various incidents set out by the Bank, it is contended that they have been enumerated out of context and that all these cases were closed by the Bank in view of the explanations given to the Bank. Shri Jha used to send intimation about his absence either through a messenger or through his brother. The allegation in respect of leaving cash counter during office hours or refusal to find the clearing differences and that all these were done to get overtime wages is denied. Shri Jha had admitted that an amount of Rs. 23,888.57 was left out, but it was due to defective machine. This incident of 1970 was fully considered by the Bank and closed. It is true that a cheque was found near Shri Jha's table, but it was not due to his negligence. Shri Jha had duly instructed Shri Gaitonde to take his signature on the hand to hand book, but the latter had forgotten to take the receipt of Rs. 10,000. It is stated that Shri Jha never denied the receipt of Rs. 10,000 from Gaitonde. It is admitted that there were shortages as indicated under, but these were on account of reasons mentioned below. The shortage of Rs. 100 on 4-6-1973 was because Shri Jha was required to hold double charge and due to pressure of work. Regarding shortage of Rs. 200 on 10-4-1973 it is not true that the responsibility thereof could not be fixed. Shri Raval to whom the money was paid by Shri Jha made good the loss. On 28-1-1974 shortage of Rs. 25 occurred because there were many bills of taxi fare to be paid to officers of the Bank and according to the practice in the Bank the paying cashier had to go to the table of every officer and pay the money. Shortage of this Rs. 25 took place in the course of this payment. On 16-2-1974 shortage of Rs. 100 was detected. On 3-9-1974 a client of the Bank presented a cheque, on reverse whereof he had written 20 notes of Rs. 100. Shri Jha due to inadvertence paid him Rs. 2,000 whereas the cheque was for Rs. 200 only. Although the client was contacted for this purpose, he refused to accept the liability and Shri Jha accepted it. Regarding the shortage found on 28-5-1976, the case is that the Manager of the Branch of the Bank had also made some payments even before the arrival of the paying cashier. According to the present system there is nothing like a joint-charge or joint-custodianship. Whatever was taken from him in writing was under threat. With regard to the soiled notes, the allegations made are denied.

5. No witness has been examined on behalf of the workman. There are, however, five witnesses on behalf of the Bank. The first witness is Shri R. G. Waghela who was the Branch Manager of the Zaveri Bazaar Branch of the Bank at the relevant time. The second witness is Shri V. P. Nair, Staff Officer of the Bank. The third witness is Shri D. D. Choksi, the paying cashier-in-charge, who was on leave from 3-5-1976 to 28-5-1976 during which interval Shri J. G. Jha had officiated in his place. Shri K. N. Gopalakrishna Rao is the fourth witness and he was the receiving cashier at the relevant time. The fifth witness is Shri P. S. Vishwanathan, Accountant in the main Office.

6. The system that was followed was that at the close of the working day, one hundred notes each of Rs. 100 denomination were made into bundles and handed over to the Manager to be kept in the strong room. Keys of the strong room as well as of the safe remained with the Accountant and the combination was known to the Manager only. In the morning the Manager, Accountant and the Cashier-in-charge remained present while taking out the cash from the safe to be given to the Pay Cashier (cashier in-charge) for the day's disbursement.

7. On the 29th morning, when Shri Choksi resumed his duties, he wanted to count the cash and notes. After counting, he reported to Shri Waghela that one bundle of Rs. 100 denomination notes contained only 90 notes instead of 100 notes, thereby making a shortage of Rs. 1,000. Counting was done by Shri Choksi in the presence of Shri Waghela and Shri J. G. Jha. Similar is the evidence of Shri Choksi and he has deposed that when he resumed his duties on the 29th morning the strong room was opened in his presence

he counted the notes in the presence of Shri Waghela and of Shri J. G. Jha. Evidence of Shri Gopalakrishna Rao (EW-4) is that later he was told that there was shortage of Rs. 1,000.

8. What Shri J. G. Jha had done was that instead of one hundred notes, the bundle was made with 90 notes only and was stapled. On the evening of 28th, Shri J. G. Jha deposited the bundles in the strong room knowing fully well that on the 29th the transaction will be conducted by Shri Choksi and at the close of the day when the shortage will be detected Shri Choksi will be held liable for the same and not Shri Jha. Such was the calculated sinister step to palm off the whole blame on a fellow worker. That such a malpractice was resorted to by Shri J. G. Jha on three previous occasions also has been deposed to by Shri V. P. Nair. He has given details of those three occasions. Shri Choksi was on leave from 18-4-1973 to 2-6-1973, during which period Shri Jha was the acting cashier-in-charge. A shortage of Rs. 100 was found and the same was made good by Shri Jha the same evening. On 3-9-1974 there was a shortage of Rs. 1,800 in Shri Jha's account who was the acting cashier in the place of Shri M. S. Trivedi. Shri Trivedi had taken casual leave on 2-9-1974. When he resumed his duties on 3-9-1974 he was unable to work as a paying cashier because of a wound on the right hand thumb and he requested the Sub-Manager not to make him work as a cashier on that day. Therefore, Shri Jha continued to work as paying cashier on 3-9-1974. The same evening while handing over the cash to the Accountant shortage of Rs. 1,800 was detected. If Shri Trivedi had taken charge as a paying cashier-in-charge on the 3rd September, 1974 and the shortage was discovered in the evening he would have been held responsible for this. Shri Jha made good the shortage and the Bank, at his request, granted him a loan for this purpose. On 16-2-1974 when Shri Choksi was on leave there was shortage of Rs. 100. 17th was a Sunday and, as such, when he resumed his duties on Monday, the 18th February 1974, there was a shortage of Rs. 100.

9. On having detected the shortage, Shri Waghela informed the Head Office on telephone about the incident and thereupon the Staff Officer, Shri V. P. Nair, accompanied by Shri P. M. Shenoy, the Manager, came to the Zaveri Bazaar Branch of the Bank. Shri Nair counted the notes and he found out the shortage of Rs. 1,000. On examination he found that the particular bundle of notes which purported to have come from the Reserve Bank of India was not the same. The top and bottom notes of the bundle contained the initial of the Reserve Bank of India official, but the bundle had been tampered with. The R.B.I. stapler pins had been removed from the bundle and the pin of the Zaveri Bazaar Branch was used. He considered that this was a serious case and fit to be handed over to the Police. He had examined the bundle in the presence of Shri Jha. That the stapler pin used in the bundle was not that of the Reserve Bank of India, but of the Zaveri Bazaar Branch of the Bank has been confirmed by Shri Waghela. Shri Waghela has deposed that Shri V. P. Nair and Shri P. M. Shenoy informed Shri Jha that the matter would be reported to the police and no threat was administered to him. Further evidence of Shri Waghela is that at first Shri Jha had repudiated about the shortage, but when he said that everything would be over if Shri Jha signed the debit note Shri Jha signed the debit note (Ext. E-13) and admitted the shortage. By saying that everything would be over Shri Waghela meant that the matter will not be reported to the police.

10. As already stated above Shri Jha has not examined himself nor any witness has been examined to explain the shortage. In his rejoinder also, he has not given any definite explanation as to how the shortage of Rs. 1,000 was happened. A suggestion was made to Shri Waghela that on the 29th morning he had made some payment before it was done by the receiving cashier. Shri Waghela has denied it. Another suggestion made to him was that since he had given a clear acquittance of Rs. 11,43,846.73 on the evening of 28-5-1976, to cover himself he had made a false report and given false evidence. He has also denied this. There is no truth in the suggestion made; rather circumstances conclusively prove that it is Shri Jha who must be held responsible for the shortage.

11. The debit note (Ext. E-13) has been signed by Shri Jha and it cannot be thrown out of consideration because in

evidence name of police has been dragged in. It is not a criminal trial and the present proceeding is in lieu of domestic enquiry. It has been held in the case of *Motising Chhagasingh Vaghela and Mehta (S.D.)* (1966 1 LLJ page 55) that the scope of the two enquiries is also different. In a criminal trial an incriminating statement made by accused is totally inadmissible in certain circumstances or before certain individuals. In a departmental enquiry the officer is not bound by such a technical rule." Moreover, at the earliest opportunity Shri Jha never complained that the debit note had been taken from him after administering threat to him; rather in his letter dated 7-6-1976 (Ext. E-12) he never complained that any undue pressure had been exercised upon him or that threat of police induced him to sign a debit note. This was the first opportunity for him to have made a grievance before the proper authorities. Failure to do so speaks volume against Shri Jha.

12. Now as to the soiled notes. Evidence of Shri Waghela is that besides shortage of Rs. 1,000 stated above Shri Choksi also reported to him in the morning of the 29th May, 1976 that ten bundles of Rs. 10 and Rs. 5 denominations contained soiled and broken notes. The practice in the Bank is not to accept such soiled and broken notes from the depositors since there is directive to the effect by the Reserve Bank of India. Only nationalised Banks, according to the witness, are allowed to accept such notes whereas the Bank in question is a foreign bank. To the question about soiled notes, Shri Jha could not give any explanation. After reporting the incident to Head Office on telephone Shri Waghela sent his report (Ext. E-10). The Bank has produced 10 bundles of soiled notes which is marked Material Ext. E-II collectively. According to Shri Waghela, some bundles of notes in Material Ext. E-II bear the initials of Shri Jha, others bear the initials slightly different from Shri Jha's initials; Yet there are some bundles which bear initials similar to the initials of the receiving cashier, Shri Rao. The bundles of soiled notes which bear the initials of Shri Jha are Material Ext. E-II(9), E-II(3) & E-II(5). In his cross-examination he has, however, admitted that the Reserve Bank of India has not issued any instructions banning acceptance of soiled notes. It was also taken out from him that he has not studied the science of handwriting and that he did not examine the initials of Shri Jha on the bundles containing soiled notes with magnifying glass. I do not think that because of these two reasons Shri Waghela should be held incompetent to recognize the initial of Shri Jha. After all Shri Jha was working under Shri Waghela and everyday hundreds of initials must have been placed before him, and if on looking at a particular initial he recognizes it as being of Shri Jha, there is nothing wonderful about it. Regarding soiled notes, Shri Waghela is corroborated by the Staff Officer, Shri V. P. Nair, (EW-2). He had examined the soiled notes and he found two portions of some notes had been cello-taped. From his knowledge he says that several notes contained in the bundle will not be accepted by the Reserve Bank of India and it will be a dead loss to the Bank. According to him, the dead loss incurred to the Bank will be more than Rs. 1,000. Shri K. N. Gopalakrishna Rao has denied that he had ever received soiled and cello-taped notes from the customers. He has also denied that any of them bear his signature. He cannot say whose initials are they. The evidence of Shri Choksi (EW-3) is that the only matter that he reported to the Manager was about the shortage. In other words, he does not corroborate Shri Waghela on the point that Shri Choksi reported to him also about that soiled notes. I do not think that simply because Shri Choksi has not deposed so evidence of Shri Waghela and Shri Nair should be disbelieved on the question of soiled notes. The Bank set out its case in paragraph No. 23(b) of their statement of claim. All that the Union stated in this regard is that "Shri Jha used to write his full name 'Jha' on the bundle of soiled notes and Shri Jha used to put his initials on the bundles which could be given to the client." It is important to observe that Shri Jha never ventured to place himself in the witness box and deny the initials that have been deposed to by Shri Waghela to be his. His failure to do so must lead to an adverse inference against him.

13. It is true that no circular of the Reserve Bank of India has been produced banning the acceptance of soiled notes by the Bank in question. It is also true that in his cross-examination Shri Waghela has admitted that the Reserve Bank has not issued any instructions banning acceptance of soiled

notes. But there is clear evidence on record that there was clear instruction of the superior authorities not to accept such notes in this Bank. As against this clear direction of the Bank Shri Jha accepted these notes, this must be held to be violation of the order of the superior officer.

14. The report that Shri Waghela sent to the Head Office is Ext. E-10. It speaks both about the shortage and the soiled notes. It begins by putting the date as 29-5-1976 (Saturday) and at the end the date is shown as 31-5-1976. Shri Waghela was cross-examined as to whether he had sent the report on 29th May or 31st May, 1976. Shri Waghela has explained by saying that he had prepared his handwritten report on 29-5-1976, but later it was sent to Head Office with his signature. When the report was shown to him, he admitted that the date on the first page should have been 31-5-1976 and not 9-5-1976. It seems that the typing was done according to what was the manuscript and the typed copy was not corrected as to the date at the top and this has resulted in the slight discrepancy. That such report was sent to the office is not disputed. It is a contemporaneous report and since it also speaks both of shortage and of soiled notes, this sufficiently corroborates the evidence of Shri Waghela and Shri Nair.

15. It was submitted on behalf of the Union that evidence of Shri Waghela cannot be relied upon as he is not a reliable person. But nothing tangible was brought to my notice to doubt the veracity of Shri Waghela. There is also nothing on record why evidence of Shri Nair should not be upheld. Looking into the facts and circumstances of the case, I feel satisfied that the shortage of Rs. 1,000 and acceptance of soiled notes was on account of Shri Jha and he must be held responsible for the same.

16. The Bank has brought sufficient materials on record to show the past record of Shri Jha. I shall presently deal with them, but I may, at this stage, refer to that part of the argument advanced on behalf of the Union, that these past records even if they indicate lapses on the part of Shri Jha, have either been condoned or action taken upon them and that they cannot be allowed to be re-opened in the present enquiry. The learned Counsel on behalf of the Bank has made it clear that it is not with a purpose to re-open those cases that evidence on these items has been led. The idea is to show the kind of past record that Shri Jha has and whether he is a fit person to be retained in service, and that regard being had to the successive and numerous incidents, the Bank has lost complete confidence in him and, therefore, the action that had been taken against him was the only proper action that should have been taken.

17. While stating the rival cases of the parties I have set out items of past misconduct of Shri J. G. Jha and the reply of the Union thereto. Some of them were specifically referred to at the time of argument and in evidence. I shall deal with them now. Regarding the incident of 3rd September, 1974, the reply of the Union is that although the cheque was for Rs. 200 only due to inadvertence Shri Jha paid Rs. 2,000 to the customer. The mistake occurred because the client had written 20 notes of Rs. 100 on the reverse side of the cheque and Shri Jha made the payment looking on them. That this explanation cannot be accepted will appear from the evidence of Shri Nair. He has deposed that on 3-9-1974 only two cheques of Rs. 200 had been presented to the Bank (Ext. E-21 & 22) and on the back of both of them it is written as 20x10. This is clearly contrary to the reply of the Union that on the reverse side of the cheque it was written as 20x100 and looking on which Shri Jha had made the mistake. Moreover, it is curious that a cashier would not look to the front of the cheque to find out the amount for which the cheque has been drawn. As regards the leave without permission, three letters Ext. E-12 (i), (ii) & (iii) were issued to Shri Jha in this connection and they show that he was cautioned by the Bank. As for the shortage of Rs. 25 incurred on 28-1-1974, the explanation given by Shri Jha is that according to the practice in the Bank the paying cashier has to go to the table of every officer and pay the taxi fare which had been incurred by the officers of the Bank. Evidence of Shri Nair is that on 28-1-1974 Shri Jha was not working in the main Office and he was in the Zaveri Bazaar Branch and that day no taxi fare was to be paid either in the

Zaveri Bazaar Branch or in the main Office. He deposed these by looking into the slips of that day (Ext. E-24 collectively).

18. There is a book wherein reports of incidents are entered by the Manager. The entry dated 26-11-1970 (Ext. E-2) says that "while going to the clearing house Shri Jha forgot to take three bundles of cheques. Then a sepoy had to rush from the clearing house to our office at 12.50 to fetch these bundles back to the clearing house." It was taken to be an example of serious oversight and gross negligence. Evidence of Shri Waghela is that he simply initiated this report and had not taken any action on it. The entry dated 19-12-1970 (Ext. E-4) says that it was reported by the sepoy of the Branch of the Bank, Mr. Sharma, that he overheard Shri Jha saying that he had purposely threw away one cheque on the floor because he was not given overtime since a long time. The evidence of Shri Waghela is that this note-book is maintained under the instruction of the Manager at the Main Office and the same is sent periodically to the Manager at the Main Office for his perusal and return. On the entry dated 4-6-1973 (Ext. E-5) it is stated that there was shortage of Rs. 100 which was made good by Shri Jha. The reply of Shri Jha on the incident in connection with the receiving cashier, Shri Gaitonde, is that he instructed Shri Gaitonde to take his signature on the hand-to-hand book, but Shri Gaitonde had forgotten to take the receipt from him. The entry dated 2-2-1974 (Ext. E-26(A)) on the Private & Confidential Report Book says that Shri Gaitonde was still in the probationary period and it was the duty of Shri Jha to give his signature for the transfer of cash to him from the receiving cashier.

19. I have found above that Shri Jha was responsible for the shortage of Rs. 1,000 and for accepting soiled and broken notes. I have also found that it was the endeavour of Shri Jha to pass on the blame to his colleagues. His past record also is such that it naturally eroded the confidence of the Bank authorities. Therefore, I find no reason to take a view different from what the Bank has taken in respect of the order passed upon him. I find there is no material to indicate victimisation or unfair labour practice or the order being mala fide.

20. Although no domestic enquiry was held by the Bank, this itself imports no infirmity. As prayed for by the Management an opportunity was given to the parties to substantiate their case and the Bank adduced the necessary evidence. The Union chose not to adduce any evidence. Thus there has been no violation of principles of natural justice. Law in this regard has been laid down by the Supreme Court in the case between the Workmen of M/s. Firestone Tyre & Rubber Co. of India (Pvt.) Ltd. and the Management & others (1973 1 LJJ page 278). It was held there that "therefore, the position is that even now the employer is entitled to adduce evidence for the first time before the Tribunal even if he had held no enquiry or the enquiry held by him is found to be defective."

21. For the reasons given above, my award is that the action of the Management of Algemeine Bank Nederland N.V., Bombay in terminating the services of Shri J. G. Jha, Cashier, Zaveri Bazaar Branch of the Bank is justified and that the workman is entitled to no relief. No order as to cost is made.

J. NARAIN, Presiding Officer

[F. No. L-12012/115/76-D.II.A]

R. P. NARULA, Under Secy.

#### MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 23rd June, 1978

**S.O. 1958.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the State Bank of India Region V and their workmen over the termination of the services of Shri Dev Prakash, Guard, Model Town Karnal Branch of the Bank which was received by the Central Government on the 9-6-78.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I. D. No. 158 of 1977

BETWEEN

The General Secretary Delhi Circle State Bank Staff Association, H. No. 2551, Sector 22-C, Chandigarh. (Shri Dev Prakash). ... Petitioner

VERSUS

The Regional Manager, State Bank of India, Region V, Parliament Street, New Delhi.

PRESENT :

Shri R. L. Malhotra and Shri J. G. Varma for the Union.

Shri S. Misra, for—the Bank.

AWARD

The Central Govt. as appropriate Govt. vide its order No. L. 12012/88/75/DII/A dated the 21st October, 1975 made a reference u/s 10 of the I.D. Act, 1947 in the following terms :

"Whether the action of the management of the State Bank of India, Region V, New Delhi in terminating the services of Shri Dev Prakash, Guard, at the Model Town Karnal Branch of the said Bank w.e.f. the 20th April, 1974 is legal and justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

The reference was originally made to Presiding Officer, Industrial Tribunal, Chandigarh and was later on transferred to this Tribunal for disposal vide order No. L. 12025(21)/76 D. II(A)/D. IV(B) dated the 13th May, 1977. After the case was received by this Tribunal usual notices were sent to the parties to appear and a statement of claim was got filed. A written statement also was filed on behalf of the Bank, and so was replication filed. However before further proceedings could take place ex-parte proceedings were ordered against the Bank as the Bank had defaulted in its appearance on the 4th February, 1978. Thereafter application for setting aside the ex-parte proceedings were filed. Shri R. L. Malhotra and Shri J. G. Varma have submitted before me today that they have no objection to the setting aside of the ex-parte order in view of the affidavit filed by the attorney for the Bank. Accordingly ex-parte proceedings against the Bank are set aside.

2. In the meanwhile on the previous hearing i.e. 7th April, 1978 Shri R. L. Malhotra and Shri J. G. Varma alongwith Shri S. Mishra came forward with a statement bringing out therein that the parties have arrived at a settlement in respect of the entire dispute and award may be made in terms of the settlement. The statement of these Gentlemen inter alia provides that 'the parties have arrived at a settlement and it has been agreed that the workman in this case may be reinstated with benefit of full back wages as per agreement dated 22-8-77 with the Federation. An award may be made accordingly. Parties be left to bear costs.'

3. In view of the statements recorded on the file an award is hereby made directing that the workman be reinstated with benefit of full back wages as per agreement dated the 22nd August, 1977 with the Federation. Parties are left to bear their own costs.

[F. No. L-12012/88/75-D. II. A

MAHESH CHANDRA, Presiding Offic.

**S.O. 1959.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Lakshmi Commercial Bank Ltd. New Delhi and the workmen over non payment of substantial salary to S. Mahesh Chand Jain which was received by the Central Government on the 6-6-78.

FOR SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I. D. No. 154 of 1977

BETWEEN

Secretary, U.P. Bank Employees' Union, 31, Hanu-mangarh, Ferozabad (Agra Distt). ... Petitioner

VERSUS

The Chairman, Lakshmi Commercial Bank Ltd., R-Block, Connaught Circus, New Delhi. ... Respondent.

AWARD

The Central Govt. vide its order No. L-12012/112/75/DI/A dated the 24th July, 1975 made a reference u/s 10 of the I.D. Act, 1947 in the following terms to Industrial Tribunal, Kanpur :

'Whether the action of the management of Lakshmi Commercial Bank Limited, New Delhi is justified in not paying substantial salary as per Bipartite Settlements to Shri Mahesh Chand Jain, clerk, Ferozabad Branch of the said Bank from 12th November, 1971 to 19th September, 1972 and in not connecting this period for purposes of increment? If not, to what relief is the said workman entitled?'

2. After usual notices were sent to the parties, the parties filed their respective statements for claim and the reply to these respective statement of claim were got filed and before issues could be framed the reference was transferred to Central Tribunal, Delhi and the Central Tribunal, Delhi framed the following issues for trial upon the pleadings of the parties :

1. Whether the cause has been validly and properly espoused?
2. Whether a valid notice of demand was served on the management raising an Industrial Dispute?
3. As in the term of reference.

3. In the meanwhile the Industrial Tribunal, Delhi relinquished the charge of the post of Presiding Officer and in consequence the case was transferred to this Tribunal for disposal and usual notices were issued to the parties to appear before this Tribunal and finally the parties appeared before this Tribunal and on the 10th April, 1978 Shri Daya Nand Munjal, Chief Personal Manager and general attorney of the Lakshmi Commercial Bank Ltd. made the following statement on this file :

'The parties have settled the matter under dispute vide settlement Ex. S/1. It bears my signatures as also the signatures of Shri Brijendra Singh State Vice President of UP Bank Employees' Union and the matter stands settled in accordance with Ex. S/1. This settlement has been acted upon and accordingly the award may be made in terms of the settlement.'

The statement of Shri Daya Nand Munjal is corroborated by Shri N. C. Sikri Advocate for the Bank. None had appeared for the workman or the Union on the date fixed in this case i.e. 27th April, 1978. I have perused the settlement. From the perusal thereof I find that certainly the matter have been settled and accordingly a no dispute award is passed in this matter leaving the parties to bear their own costs.  
Dated : the 27th April, 1978

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

[F. No. L-12012/112/75-D. II. A.]

S.O. 1960.- In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute

between the employees in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen over fixation of the basic pay of Shri N. G. Shrimali, Cashier-cum-Godown Keeper Khandwa Branch of the Bank which was received by the Central Government on the 9-6-78.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(17)/1978

PARTIES

Employers in relation to the management of Punjab National Bank M. P. Region, Bhopal and their workmen represented through the M. P. Bank Employees Association, Yeshwant Road, City Post Office Building, Indore (M.P.)

APPEARANCES

For Union ... S/Shri P. N. Sharma and B. L. Shah.

For Management ... Shri R. P. Raizada.

INDUSTRY : Bank ... DISTRICT : Bhopal (M.P.)

Dated : June 2, 1978.

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/115/77-D. II. A. Dated 30th March, 1978, for the adjudication of the following industrial dispute by this Tribunal :—

"Whether the action of the Regional Manager, Punjab National Bank Bhopal in fixing the basic pay of Shri N. G. Shrimali, Cashier-cum-Godown Keeper Khandwa Branch of the Bank at Rs. 190 p.m. his appointment on probation on 1-11-71 without giving the benefit of his past service towards increment is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. It is not disputed in the pleadings that Mr. Shrimali was engaged as temporary Godown Keeper with effect from 26th October, 1967 and he continued in that capacity upto 9th October, 1971 with the following breaks :

29-7-1970 to 2-8-1970	5 days break
15-8-1970 to 17-8-1970	3 days break in holidays
23-8-1970 to 25-8-1970	3 days break
28-8-1970 to 30-8-1970	3 days break
20th September, 1970	1 day's break (Sunday)
18th October, 1970	1 day's break (Sunday)
20-10-1970 to 27-10-1970	8 days break
10-10-1971 to 31-10-1971	22 days break

It is further admitted by the parties before me that whenever these breaks were given no retrenchment compensation was paid to the workman. After the last break of 22 days the workman was taken as probationer and was placed at the initial stage of the scale meant for a graduate employee.

3. Applicant's case is that the breaks were artificial and not legal hence he shall be deemed to have continued in service. He was in the employment of the Bank and not in the employment of any other private party. Therefore while fixing the salary on appointing him as a probationer Bank should have given the benefit of his past services by way of four increments.

4. The case of the Bank is that on account of the break in service his appointment was a fresh appointment as probationer. The benefit of past services could not be given to him more so because during that period he was working for the private parties, i.e. looking after the godowns of those private parties who mortgaged the same with the Bank.

5. The parties have conceded that no evidence is necessary in the case and the matter can be decided on the legal position emerging from the pleadings. Admittedly Mr. Shrimali was being paid by the Bank. He was under the disciplinary jurisdiction of Bank officials. His appointment was in a scale fixed and recognised by the Bank. He earned two increments during that period of temporary service. There was no direct contract between Mr. Shrimali and any borrower party. Looking to all the circumstances it is clear that in spite of the fact that his pay was to be reimbursed by the borrower which was an arrangement inter se between the Bank and the borrower. Mr. Shrimali was very much an employee of the Bank only.

6. It is admitted in management's written statement that Mr. Shrimali started the temporary service as Godown Keeper on 26-10-1967 and he earned two annual increments upto 26-10-1969. This means that the Bank admitted that he was in continuous employment of the Bank till 26-10-69. Under the circumstances the artificial break of 5 days given on 29-10-1970 without payment of retrenchment compensation was illegal being in breach of Section 25F of Industrial Disputes Act because admittedly he had by that time completed 12 months employment and more than 240 days attendance. Similarly in turn the other break without payment of retrenchment compensation would be deemed to be illegal, inoperative and non est including the last break given on 10-10-1971 to 31-10-1971 and he will be deemed to have continued in service.

7. When a temporary employee in continuation of his temporary service, is inducted into permanent service, either by an automatic process of expiry of certain period as in case of Category (i) Godown keepers or by way of qualifying in regular recruitment in case of Category (ii) Godown keepers, the temporary service projects and continues further, into the permanent service and the

increments already earned or those increments which he should have earned the continuity of temporary employment shall not stand forfeited on being appointed in a permanent capacity. Where there is a gap between the temporary employment and the permanent appointment brought about by a legal and valid termination of temporary service the spell of the temporary service will lapse with the lapse of the service on account of the said legally valid termination. But where the temporary service continues and projects into the permanent one as said above the increments earned during the course of temporary service shall survive under the benign shadow of continuity of that temporary service into the permanent one. This principle of relating back can be deducted from the provision that for the purposes of confirmation the period of probation shall be adjusted towards the temporary service.

8. It is, therefore, held that the fixation of Mr. N. G. Shrimali at Rs. 190 on 1-11-1971 without giving the benefit of his past services towards increments was not justified. He shall be refixed after giving the benefit of his past temporary services which shall be deemed to have continued from 26-10-1967 to 31st October, 1971. Arrears of salary arising from such refixation shall be paid. The salary for the periods of artificial breaks shall also be paid to the workman as those breaks were unjustified and illegal. The management shall further pay Rs. 50 as costs to the Union. The award is given accordingly.

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

Date : 2-6-1978.

[F. No. L-12012/115/77-D.I.A.]

R. P. NARULA, Under Secy.

